दैनिक
स्वर्णिम प्रदेश

PRN: MCN/329/2025-2027
epaper.swarnimpradesh.in

संरक्षक: मां वैष्णो देवी

विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें

अगर आप अपने विशेष अवसरों को खास बनाना चाहते हैं या महत्वपूर्ण सूचनाओं को व्यापक जनता तक पहुँचाना चाहते हैं, तो दैनिक स्वर्णिम प्रदेश आपके लिए सही मंच है। चाहे जन्मदिन की बधाई हो, शादी की सालगिरह, गुमशुदगी की सूचना, कानूनी नोटिस या कोई अन्य व्यक्तिगत और व्यावसायिक विज्ञापन, हम आपके संदेश को सही तरीके से पहुंचाने में मदद करेंगे। आपके विज्ञापन से समाचार पत्र को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, जो इसे और बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगी।

ईमेल: swarnimpradesh@yahoo.com
या वाट्सऐप नं. 8898271111

वर्ष : 8 • अंक : 300 • मुंबई, सोमवार 18 मई, 2026 • पृष्ठ : 6 • मूल्य: 2 रुपये • संपादक : सुनील कुमार तिवारी • Email: swarnimpradesh@yahoo.com www.swarnimpradesh.in

स्वीडन पहुंचे पीएम मोदी: व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग पर जोर

संवाददाता

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी पांच देशों की छह दिवसीय विदेश यात्रा के तीसरे दिन रविवार को नीदरलैंड से स्वीडन पहुंचे। स्वीडन में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य भारत और स्वीडन के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और रक्षा सहयोग को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत-स्वीडन मित्रता को नई दिशा देने पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान रहेगा। प्रधानमंत्री ने अपने एक अन्य संदेश में कहा कि वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन के साथ 'यूरोपीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन' में यूरोप के प्रमुख उद्योगपतियों और व्यापारिक नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत और यूरोप के बीच निवेश संबंधों को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा

कि भारत और यूरोप के बीच आर्थिक साझेदारी को नए अवसर प्रदान करने के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इस यात्रा से भारत और स्वीडन के संबंधों को नई गति मिलेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पांच देशों की छह दिवसीय यात्रा के तीसरे दिन नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ नीदरलैंड के ऐतिहासिक अफ़्सलुइटडिज्क बांध का दौरा किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने जल प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण और समुद्री जल को रोककर भूमि तथा मीठे पानी के संसाधनों के विकास से जुड़ी परियोजनाओं की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर साझा करते हुए कहा कि जल संसाधन प्रबंधन ऐसा क्षेत्र है, जिसमें नीदरलैंड ने अग्रणी कार्य किया है और पूरा विश्व उससे बहुत कुछ सीख सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें अफ़्सलुइटडिज्क परियोजना की प्रमुख विशेषताओं को समझने का अवसर मिला और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री रॉब जेटन का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और अंतर्देशीय जलमार्ग नेटवर्क के विस्तार के उद्देश्य से आधुनिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड के बीच सहयोग को और मजबूत किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इसे महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ अफ़्सलुइटडिज्क बांध का दौरा किया, जो जल प्रबंधन, बाढ़ सुरक्षा और मीठे पानी के भंडारण में डच इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और नवाचार का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह दौरा गुजरात की कल्पसर परियोजना के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य खंभात की खाड़ी के निकट मीठे पानी का विशाल भंडार और बांध विकसित करना है। इससे जलवायु अनुकूलन, जल प्रौद्योगिकी और सतत अवसंरचना के क्षेत्र में भारत-नीदरलैंड सहयोग की नई संभावनाओं को भी बल मिलेगा। उल्लेखनीय है कि अफ़्सलुइटडिज्क नीदरलैंड का प्रमुख बांध और पुल है, जिसका निर्माण वर्ष 1927 से 1932 के बीच किया गया था। यह लगभग 32 किलोमीटर लंबा बांध उत्तरी हॉलैंड के डेन ओएवर को फ्रीसलैंड प्रांत के ज्यूरिख गांव से जोड़ता है। इस बांध ने उत्तरी सागर की खारे पानी की खाड़ी जुइडरज़ी को बंद कर उसे आईजेलमीर नामक मीठे पानी की विशाल झील में परिवर्तित कर दिया।

अश्विनी वैष्णव ने मुंबई-बेंगलुरु एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, जल्द शुरू होगी वंदे भारत स्लीपर सेवा

संवाददाता

नई दिल्ली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को बेंगलुरु-मुंबई एक्सप्रेस रेल सेवा को आभासी माध्यम से हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि इससे कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच रेल संपर्क को मजबूती मिलेगी। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर सेवा जल्द शुरू की जाएगी।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक की लंबे समय से लंबित मांगों को अब पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में रेलवे के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे कर्नाटक में रेल परियोजनाओं के कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कर्नाटक के 61 रेलवे स्टेशनों का 2,160 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है। इनमें से 9 स्टेशनों का कार्य पूरा हो चुका है। बेंगलुरु कैंटोनमेंट स्टेशन का 485 करोड़ रुपये तथा यशवंतपुर स्टेशन का 367 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से कर्नाटक में लगभग 1,750 किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई गई हैं। हासन-मंगलुरु खंड में जटिल विद्युतीकरण कार्य भी पूरा कर लिया गया है और परीक्षण जारी है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना के चारों गलियारों पर कार्य चल रहा है। बैयप्पनहल्ली-चिक्कबनावरा और हीलालिगे-राजनुकुंटे गलियारों में भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है तथा स्टेशनों का निर्माण कार्य जारी है। केएसआर बेंगलुरु-देवनहल्ली मार्ग को राज्य सरकार और रेलवे की संयुक्त मंजूरी मिल चुकी है और भू-तकनीकी सर्वेक्षण पूरा हो गया है। केंगेरी-व्हाइटफील्ड मार्ग को भी हाल में स्वीकृति मिली है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कर्नाटक में इस समय 12 जोड़ी वंदे भारत रेलगाड़ियां संचालित हो रही हैं। बेंगलुरु-मंगलुरु मार्ग पर परीक्षण चल रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों तक संपर्क और बेहतर होगा। बेंगलुरु को हैदराबाद और चेन्नई से जोड़ने वाले बुलेट रेल गलियारों को भी मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने कहा कि नई बेंगलुरु-मुंबई रेल सेवा देश के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में से एक पर यात्रियों को बड़ी सुविधा देगी। थानिसंद्रा में 270 करोड़ रुपये की लागत से वंदे भारत स्लीपर अनुरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, जबकि एसएमवीटी बेंगलुरु में 52.73 करोड़ रुपये की लागत से चेयर कार अनुरक्षण सुविधा विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैयप्पनहल्ली-होसुर दोहरीकरण, बेट्टाहलासुरु-राजनुकुंटे परियोजना तथा बेंगलुरु क्षेत्र में चौगुनीकरण कार्यों के जरिए रेल क्षमता बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा विभिन्न प्रमुख रेल खंडों पर 6,396 करोड़ रुपये की लागत से स्वचालित संकेत प्रणाली विकसित की जा रही है। वी सोमन्ना ने कहा कि कर्नाटक को इस बार 7,748 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड रेल बजट आवंटन मिला है। वर्ष 2014 के बाद से राज्य में 3,840 किलोमीटर रेल लाइनों का विकास तथा 3,742 किलोमीटर रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया गया है।

विवादित ट्वीट से बढ़ीं अनुराग कश्यप की मुश्किलें, चलेगा आपराधिक मामला

संवाददाता

सूरत। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर ब्राह्मण समाज को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में अब सूरत की अदालत में उनके खिलाफ आपराधिक मामला चलाया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता की शिकायत पर कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाई है। मामले के अनुसार, 19 मार्च 2025 को अनुराग कश्यप ने सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट की थी, जिसे लेकर ब्राह्मण समाज में नाराजगी फैल गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि पोस्ट के विरोध में आदित्य दत्ता नामक व्यक्ति ने कश्यप से टिप्पणी हटाने और संयम बरतने की अपील की थी, लेकिन इसके जवाब में कश्यप ने कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद देशभर में विरोध शुरू हुआ और कई स्थानों पर शिकायतें दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी क्रम में सूरत के वरिष्ठ

अधिवक्ता कमलेश रावल ने अदालत में आपराधिक शिकायत दायर की। कोर्ट ने शिकायत स्वीकार करते हुए अनुराग कश्यप को समन जारी कर पेश होने के निर्देश दिए थे। शिकायत पक्ष के अनुसार, समन जारी होने और मुंबई स्थित वकील के माध्यम से सूचना मिलने के बावजूद अनुराग कश्यप अदालत में उपस्थित नहीं हुए। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि आरोपी को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद सूरत कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196, 352 और 353(2) के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

शुभेंदु अधिकारी का ममता-अभिषेक पर हमला, आरजी कर केस में सबूत मिटाने का आरोप

संवाददाता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर दौरे से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोला। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार ने मुख्य आरोपितों को बचाने और सबूत मिटाने की कोशिश की थी। अभिषेक बनर्जी की कथित संपत्तियों की जांच कराने की भी चेतावनी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह "दोनों कांडों का अंत देखकर ही छोड़ेंगे।" मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी का यह पहला जिला दौरा था। वह फलता विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में दक्षिण 24 परगना पहुंचे थे। यहां उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा की और उससे पहले डायमंड हार्बर पुलिस जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने

घोषणा की कि ममता बनर्जी सरकार द्वारा गठित पुलिस वेलफेयर बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग किया जा रहा है। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आरजी कर मामले में पूर्व मुख्यमंत्री के इशारे पर कई पुलिस अधिकारियों ने अत्याचार किया, सबूत मिटाने का प्रयास किया और पीड़िता की मां को रिश्वत देने तक की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इसी वजह से तीन आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया गया है। शुभेंदु ने यह भी कहा कि दक्षिण 24 परगना जिले में भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा उम्मीदवार विश्वजीत पाल पर हमले के मामले में बारुईपुर थाने के प्रभारी और कैनिंग में भाजपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार के आरोप में एक अन्य पुलिस अधिकारी को निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उन्होंने डायमंड हार्बर पुलिस जिले के अधिकारियों से कॉल रिकॉर्ड और व्हाट्सऐप चैट जमा करने को कहा है। उनका आरोप था कि "भतीजे के पीए" के निर्देश पर फलता, डायमंड हार्बर और दक्षिण 24 परगना में अत्याचार किए गए। उन्होंने कहा कि जब जांच एजेंसियों के सामने विनीत गोयल, इंदिरा मुखोपाध्याय और अभिषेक गुप्ता के कॉल रिकॉर्ड और चैट सामने आएंगे, तब पूर्व सरकार की "कुकृत्य" उजागर होंगे। अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने कोलकाता नगर निगम से "लिप्स एंड बाउंड्स" नामक कंपनी से जुड़ी संपत्तियों की सूची मंगवाई है।

राहुल गांधी ने नीट-यूजी पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा

संवाददाता

नई दिल्ली। नीट-यूजी परीक्षा पत्र लीक मामले को लेकर सियासी विवाद लगातार गहराता जा रहा है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पर निशाना साधते हुए उनका इस्तीफा मांगा है। राहुल गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा कि वर्ष 2024 और 2026 दोनों में नीट परीक्षा पत्र लीक हुआ लेकिन शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि हर बार जांच एजेंसियों और समितियों के गठन के बावजूद परीक्षा प्रणाली में सुधार नहीं हो पा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि वर्ष 2024 में नीट परीक्षा पत्र लीक हुआ था, परीक्षा रद्द नहीं हुई, मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया और मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी गई थी। वर्ष 2026 में भी परीक्षा पत्र लीक हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी, फिर से सीबीआई जांच कर रही है और एक अन्य समिति गठित की जा रही है।

उन्होंने कहा कि बार-बार परीक्षा पत्र लीक क्यों हो रहे हैं, इस मुद्दे पर सरकार चुप क्यों है और लगातार विफल हो रहे शिक्षा मंत्री को पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि नीट-यूजी 2026 परीक्षा तीन मई को आयोजित की गई थी। परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक होने के आरोप सामने आने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने परीक्षा रद्द कर दी थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी। जांच एजेंसी ने मामले में अब तक कई आरोपितों की गिरफ्तारी की है। जांच में प्रश्नपत्र लीक, अभ्यर्थियों से धन वसूली और विशेष कोचिंग सत्रों के माध्यम से प्रश्न उपलब्ध कराने जैसे आरोपों की पड़ताल की जा रही है।

बिहार: पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, एक ही परिवार के चार समेत पांच की मौत

संवाददाता

सीवान। बिहार में सीवान जिले के सिसवन थाना क्षेत्र के ग्यासपुर गांव के एक ही परिवार के चार सदस्यों समेत पांच लोगों की उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर हुए भीषण सड़क हादसे में शनिवार को दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम पसर गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतकों की पहचान ग्यासपुर गांव निवासी प्रेम लाल श्रीवास्तव के पुत्र मनीष श्रीवास्तव, उनकी पत्नी कंचन देवी, 16 वर्षीय पुत्री आस्था कुमारी तथा 11 वर्षीय पुत्री अदिति कुमारी के रूप में हुई है। वहीं एक अन्य मृतक को परिवार का संबंधी बताया जा रहा है। बताया जाता है कि मनीष श्रीवास्तव हरियाणा के फरीदाबाद में परिवार के साथ रहते थे। चार दिन पूर्व वे अपने मामा के घर

छपरा जिले के मढ़ौरा पहुंचे थे, जहां उनके नाना का ब्रह्मभोज कार्यक्रम था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद शनिवार को मनीष अपने माता-पिता को लेकर छपरा शहर पहुंचे और वहां अपने ससुराल पक्ष के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद मनीष ने अपने माता-पिता को सार्वजनिक वाहन से गांव भेज दिया और स्वयं पत्नी व दोनों बेटियों के साथ कार से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बताया जाता है कि जैसे ही उनकी कार उत्तर प्रदेश के कंधरापुर थाना क्षेत्र स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के माइलस्टोन 238 के पास पहुंची, तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार सड़क किनारे खड़े राजस्थान नंबर के ट्रक से जा टकराई।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी से निर्मित कैंसर अस्पताल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बनेगा मील का पत्थर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

संवाददाता

पुणे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुणे महानगरपालिका की भूमि पर सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ निर्मित अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी पहल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से स्थापित यह केंद्र स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।

रविवार को मुख्यमंत्री यह बात पुणे मुनसिपल कॉर्पोरेशन और आपुलकी हेल्थकेअर के संयुक्त उपक्रम से स्थापित अत्याधुनिक कैंसर केंद्र के लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, महापौर मजुषा नागपुरे, सांसद मेधा कुलकर्णी,

विधायक भीमराव तापकीर, विधायक राहुल कुल, उपमहापौर परशुराम वाडेकर तथा महानगरपालिका आयुक्त नवकिशोर राम उपस्थित थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि कैंसर के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। समय पर जांच और उपचार मिलने पर यह बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है। लेकिन उपचार में देरी होने पर मरीजों को लंबे समय तक इलाज कराना पड़ता है और आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं में कैंसर उपचार को शामिल किया है, ताकि आम नागरिकों को समय पर उपचार मिल सके। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर "कैंसर ग्रिड" विकसित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से राज्य के मरीजों को अधिक सक्षम और सुलभ उपचार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह ग्रिड राज्यभर में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी और समन्वित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने पुणे मुनसिपल कॉर्पोरेशन और आपुलकी हेल्थकेअर द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से शुरू किए गए इस उपक्रम की सराहना भी की। कार्यक्रम में महानगरपालिका के पदाधिकारी, फाउंडेशन के प्रतिनिधि, चिकित्सा अधिकारी तथा नागरिक उपस्थित थे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने अस्पताल का निरीक्षण किया और विभिन्न उपचार विभागों, अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों तथा मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली।

संपादकीय

डॉलर बचाने की चुनौती

वैश्विक स्तर पर तेल-गैस संकट गहराने, सोने के बढ़ते आयात और विदेश यात्राओं में भारतीयों के बढ़ते खर्च के चलते भारत के सामने विदेशी मुद्रा बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट बाधित होने से ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ा है, जिससे आयात बिल बढ़ने की आशंका है। इसी स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन बचाने, विदेश यात्रा कम करने और एक साल तक सोना न खरीदने जैसी अपील कर देशवासियों को मितव्ययिता अपनाने का संदेश दिया है।

वैश्विक तेल संकट, सोने के आयात और विदेश में भारतीयों के खर्च के कारण भारत को विदेशी मुद्रा बचाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईंधन बचाने, विदेश यात्रा कम करने और सोना न खरीदने की अपील की है, साथ ही सड़क जाम और आयातित वस्तुओं के विकल्प पर भी जोर दिया गया है। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के कारण ढाई माह से होर्मुज समुद्री मार्ग बाधित होने से विश्व में गैस और तेल का जो संकट खड़ा हुआ, वह अब तक जारी है। इसका प्रभाव भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ा है। भारत के लिए होर्मुज स्ट्रेट से बड़े पैमाने पर तेल और गैस की आपूर्ति होती थी। पिछले ढाई माह से इस आपूर्ति में खासी कमी आई है। जैसे-तैसे तेल और गैस से लैस कुछ जहाज होर्मुज स्ट्रेट से निकलकर भारत आ पा रहे हैं। यह अलग बात है कि अभी तक भारत में पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर कोई गंभीर संकट खड़ा नहीं हुआ। भारत सरकार की इसके लिए सराहना करनी होगी कि उसने तेल-गैस की जो वैश्विक चुनौती खड़ी हुई, उसका सामना बखूबी किया। जब तमाम देशों ने पेट्रोल और डीजल के दाम होर्मुज स्ट्रेट बाधित होने के चंद दिनों बाद ही बढ़ा दिए थे, तब भारत ने करीब 75 दिन बाद बढ़ाए और वह भी अन्य देशों की तुलना में बहुत कम। ऐसा करना इसलिए आवश्यक हो गया था, क्योंकि तेल कंपनियों का घाटा बढ़ रहा था। विश्व में जब भी किसी वस्तु की किल्लत होती है तो उसकी कीमतें बढ़ती ही हैं। यदि पश्चिम एशिया संकट सुलझा नहीं तो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें और बढ़ सकती हैं। इससे आयात बिल बढ़ेगा। इसे देखते हुए ही पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों से अपील की कि वे पेट्रोल और डीजल की बचत करें, विदेश यात्राएं कम करें, वर्क फ्राम होम काम करें और कम से कम एक वर्ष तक सोना न खरीदें। सब जानते हैं कि आम भारतीय सुरक्षित निवेश के रूप में सोना खरीदने को प्राथमिकता देते हैं। इस समय विश्व के किसी देश में लोगों के पास सबसे अधिक सोना है तो वह भारतीयों के पास है। एक आकलन के अनुसार लगभग 40 हजार टन सोना भारतीय घरों में है। चूंकि भारत में सोने का उत्पादन बहुत कम होता है, लिहाजा उसका आयात होता है। पिछले वर्ष भारत ने करीब 72 अरब डालर का सोना खरीदा। डालर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से सोने के आयात में विदेशी मुद्रा की खपत कहीं अधिक हो रही है। बहुत कम भारतीयों की ओर से अपने सोने को गिरवी रखकर बैंकों से पैसा लेने के कारण यह एक तरह से डेड इन्वेस्टमेंट के रूप में ही पड़ा रहता है। भारतीयों में सोना खरीदकर घर में रखने की ललक के पीछे यह माना जाता है कि उनका बैंकिंग व्यवस्था और शेयर बाजार पर अधिक भरोसा नहीं। इससे भी इन्कार नहीं कि कई लोग अपनी दो नंबर की कमाई सोने में खपाते हैं। चूंकि भारत में आम जन का सोने के प्रति विशेष मोह है, इसलिए सरकार को बैंकिंग व्यवस्था और शेयर बाजार में निवेश को लेकर लोगों के भरोसे की कमी के कारणों पर सोचना चाहिए। विदेशी मुद्रा की सबसे अधिक खपत पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में होती है। इसका कारण अर्थव्यवस्था का तेजी से बढ़ना है, लेकिन तथ्य यह भी है कि भारत में शायद वाहनों का माइलेज सबसे कम होगा। एक लीटर पेट्रोल या डीजल में भारतीय वाहन सबसे कम सफर कर पाते हैं। इसका कारण हमारी सड़कों का आधारभूत ढांचा कमजोर होना और उनके निर्माण की खराब डिजाइनिंग है। रही-सही कसर सड़कों पर अतिक्रमण के चलते लगने वाले जाम से पूरी हो जाती है। अक्सर टोल-नाकों पर भी जाम लगता है। इस सबके चलते लाखों लीटर पेट्रोलियम उत्पादों की बर्बादी होती है। ऐसा नहीं है कि उन समस्याओं से पार नहीं पाया जा सकता, जिनके चलते जाम लगता है अथवा वाहन धीमी गति से चल पाते हैं, लेकिन इसके लिए जैसी राजनीतिक और सामाजिक इच्छाशक्ति चाहिए, उसका घोर अभाव ही दिखता है। बड़े शहरों की बात तो दूर, अब छोटे-छोटे शहरों में भी जाम लगता है और कभी-कभी तो घंटों तक, लेकिन इसकी चिंता न तो केंद्र सरकार करती है, न राज्य सरकारें और और न ही उनके स्थानीय निकाय। प्रधानमंत्री की अपील पर कई नेताओं ने अपनी कारों का काफिला छोटा किया है या फिर मोटरसाइकिल, मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं। ऐसे कदम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए तो ठीक हैं, पर ईंधन की खपत में कोई ठोस कमी तो जाम की समस्या के समाधान से ही होगी। हाल में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि यदि दिल्ली में एमसीडी के टोल नाकों को पूरी तरह इलेक्ट्रानिक कर दिया जाए तो इससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि जाम से छुटकारे के चलते ईंधन की बचत भी होगी। दिल्ली की तरह देश के दूसरे शहरों में न जाने कितने ऐसे टोल नाके और ट्रैफिक बाधित करने वाले चोक पाइंट होंगे, जहां अरबों रुपये का ईंधन बर्बाद होता है। सरकारी विभागों को यह समझना होगा कि जाम से मुक्ति पाकर अरबों रुपये का ईंधन बचाया जा सकता है। इससे विदेशी मुद्रा भी बचेगी। चूंकि अपने देश में सड़कों पर अतिक्रमण आम है, इसलिए जाम लगता है और जब जाम लगता है तो ईंधन की बर्बादी होती है। सड़कों पर अतिक्रमण करना अपने यहां एक सामाजिक समस्या बन गई है। इस समस्या से निजात पाने के लिए भी राजनीतिक एवं प्रशासनिक इच्छाशक्ति का अभाव दिखता है। हमारी नौकरशाही समस्याओं के समाधान के दीर्घकालिक उपायों पर गंभीरता से कम ही विचार करती है। भारत में एक बड़ी आबादी ऐसी है, आर्थिक संपन्नता के मामले में जिसकी तुलना कई यूरोपीय देशों से की जा सकती है। आज यह समर्थ आबादी शायद ही मितव्ययिता का परिचय दे पाए। बेहतर होगा सरकार इस बारे में सोचे कि कैसे ऐसे विकल्प तैयार हों, जिससे यह तबका विदेशी मुद्रा की बचत कर सके। तभी शायद वह इस तोहमत से बच सकेगा कि वह अनावश्यक खर्चे करता है। तमाम भारतीय घूमने या खरीदारी के लिए विदेश जाते हैं। इसमें अच्छी-खासी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसके अतिरिक्त देश में इलेक्ट्रानिक्स और अन्य आयातित वस्तुओं की खरीद भी खूब होती है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि देश में भारतीयों की जरूरत की तमाम वस्तुएं निर्मित नहीं होतीं या उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। जब तक आयातित सामग्री के बेहतर विकल्प नहीं होंगे, तब तक समाज का अभिजात्य वर्ग विदेशी मुद्रा खर्च पर नियंत्रण में सहयोग नहीं दे पाएगा।

पुस्तक समीक्षा: विसंगतियों के आइने में समकालीन यथार्थ बनाम चूं चूं की खोज

डॉ.विभा खरे

वरिष्ठ व्यंग्यकार विवेक रंजन श्रीवास्तव का व्यंग्य लेखन आज के दौर की विसंगतियों, राजनीतिक पाखंड और सामाजिक दोहरेपन पर एक करारी चोट है। उनकी लेखनी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे केवल समस्याओं को उजागर नहीं करते, बल्कि मानवीय प्रवृत्तियों का गहराई से विश्लेषण भी करते हैं। लेखक ने 'आठवीं पीढ़ी की व्यवस्था' जैसे व्यंग्यों के माध्यम से राजनीति में व्याप्त वंशवाद और संचय की प्रवृत्ति पर तीखा प्रहार किया है। वे बताते हैं कि कैसे एक नेता अपनी सात पीढ़ियों का इंतजाम करने के बाद आठवीं पीढ़ी के लिए अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च करने की जुगत में रहता है। 'जुगाड़ मतलब टैक्टफुलनेस' और 'सेवा का मेवा' जैसे लेखों में लेखक ने हमारे समाज की 'जुगाड़' संस्कृति और परोपकार के नाम पर चल रहे व्यापार को बड़ी चतुराई से उकेरा है। उदाहरण के लिए, 'सेवा का मेवा' में वे दिखाते हैं कि कैसे पुराने कॉलेज मित्र अब 'प्रभु' बनकर सेवा के नाम पर मेवा खा रहे हैं। 'डीप फेक है यह दुनिया' के जरिए लेखक ने आधुनिक तकनीक के खतरों और हमारी 'डिजिटल दुकानदारी' पर व्यंग्य किया है, जहाँ असल और नकल का भेद करना मुश्किल हो गया है। विवेक जी सहज और पठनीय शैली के धनी हैं। उनकी भाषा सरल, बोलचाल की और व्यंग्य की धार से भरपूर होती है। वे 'जुगाड़' जैसे देसी शब्दों को 'टैक्टफुलनेस' जैसे मैनेजमेंट के भारी-भरकम शब्दों से जोड़कर पाठकों को

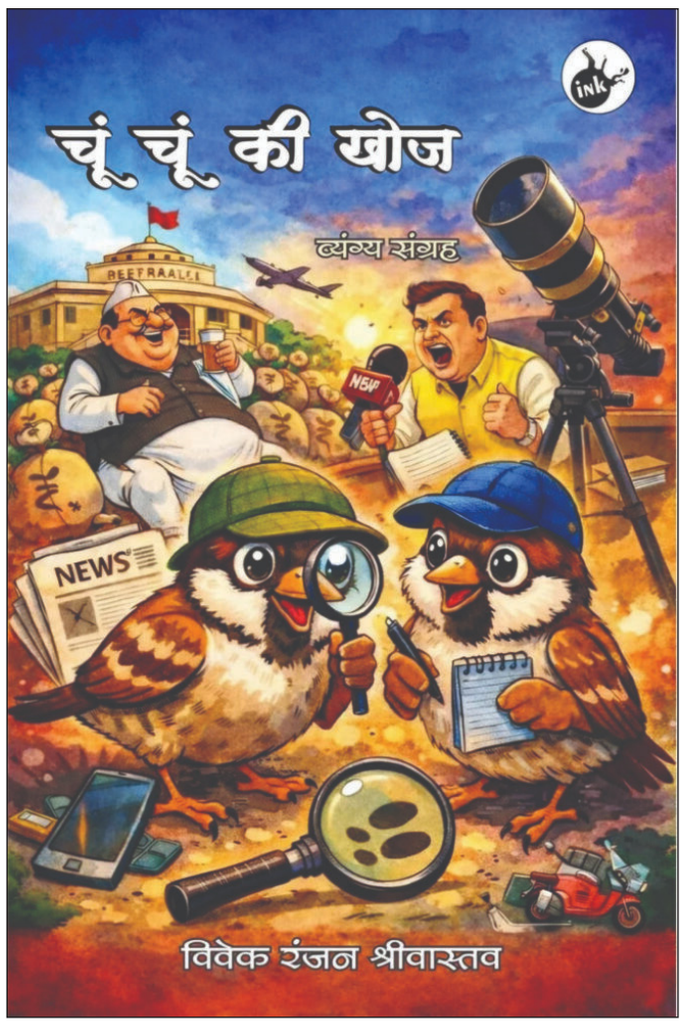

एक साथ सटायर विट और ह्यूमर से हँसने और सोचने पर मजबूर कर देते हैं। विवेक रंजन के व्यंग्य वैश्विक कैनवास पर सहजता से प्रकट होते हैं। उनका लेखन उन लोगों के लिए एक आईना है जो समाज की विकृतियों को देखना और समझना चाहते हैं। चूं चूं की खोज, 75 मजेदार समकालीन व्यंग्य लेखों का संग्रह है । यह आम आदमी का मनोरंजन तो करता ही है, पाठक को अपने आस-पास की दुनिया के प्रति अधिक जागरूक और संवेदनशील भी बनाता है। किताब पैसा वसूल और संग्रहणीय है।

जयराम रमेश ने ग्रेट निकोबार परियोजना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा पत्र

संवाददाता

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने केंद्र सरकार की ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। उन्होंने इसमें कहा कि इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उचित ठहराने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि इसके मौजूदा स्वरूप से बड़े स्तर पर पारिस्थितिक क्षति होने की आशंका है।

पत्र में कहा गया कि उन्होंने इससे पहले 10 मई को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री को तथा 13 मई को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री को भी पत्र लिखकर परियोजना से जुड़े पर्यावरणीय और वन अधिकार अधिनियम संबंधी मुद्दे उठाए थे। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और भारत की सामरिक शक्ति को विश्वसनीय रूप से प्रदर्शित करने की आवश्यकता पर कोई मतभेद नहीं हो सकता, लेकिन इसके नाम पर ऐसी परियोजना को आगे बढ़ाना उचित नहीं है, जिससे व्यापक पर्यावरणीय नुकसान हो। पत्र में जयराम रमेश ने

कहा कि ग्रेट निकोबार द्वीप के कैंपबेल बे में स्थित आईएनएस बाज को जुलाई 2012 में कमीशन किया गया था, लेकिन मौजूदा रनवे की लंबाई को तीन गुना बढ़ाने और नौसैनिक जेट्टी बनाने की योजनाएं पिछले लगभग पांच वर्षों से मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही हैं। इन योजनाओं का पर्यावरण पर प्रभाव भी मौजूदा ग्रेट निकोबार परियोजना की तुलना में काफी कम होगा। उन्होंने कहा कि अंडमान एवं निकोबार कमांड की कई मौजूदा सैन्य परिसंपत्तियों का विस्तार भी अपेक्षाकृत कम पर्यावरणीय क्षति के साथ किया जा सकता है। इनमें आईएनएस कार्दीप, आईएनएस कोहासा, आईएनएस उत्क्रोश, आईएनएस जरावा और कार निकोबार वायुसेना स्टेशन शामिल हैं। जयराम रमेश ने कहा कि ग्रेट निकोबार परियोजना के तहत प्रस्तावित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह और टाउनशिप देश की सैन्य क्षमता को किसी प्रकार नहीं बढ़ाते, लेकिन अब इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर उचित ठहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रेट निकोबार परियोजना अपने वर्तमान स्वरूप में पारिस्थितिक तबाही का नुस्खा है। उन्होंने रक्षा मंत्री से आग्रह किया कि वे उन वैकल्पिक प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करें, जिनका सुझाव कुछ प्रतिष्ठित नौसेना अधिकारियों ने भी अपने लेखों और विश्लेषणों में दिया है।

पेपरलेस न्याय व्यवस्था भविष्य के लिए महत्वपूर्ण एवं आवश्यक : न्यायमूर्ति सूर्यकांत

संवाददाता

भोपाल। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि डिजिटल परिवर्तन और पेपरलेस न्याय व्यवस्था भारतीय न्यायपालिका के भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अदालतों की पहचान अब लाल कपड़ों में बंधी भारी-भरकम फाइलों से नहीं, बल्कि स्मार्ट तकनीक से होगी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत शनिवार को जबलपुर में महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा आयोजित "डिजिटल ट्रांसमिशनः एडवांसिंग पेपरलेस लीगल सिस्टम" विषय पर आयोजित विधिक व्याख्यान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौर को एक ऐतिहासिक मोड़ बताते हुए कि उस संकटकाल में वर्चुअल हियरिंग और ई-फाइलिंग से न्याय प्रणाली को नई दिशा मिली। उच्चतम न्यायालय ने अब 'मिसलेनियस डेट्स' पर पूरी तरह वर्चुअल हियरिंग का निर्णय लिया है, जिससे वकीलों को घर बैठे दलीलें रखने की सुविधा मिलेगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अपने 37 वर्ष की आयु में महाधिवक्ता बनने

के दौर को याद करते हुए बताया कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व. अरुण जेटली के सहयोग से उन्होंने देश का पहला पूर्णतः कंप्यूटरीकृत महाधिवक्ता कार्यालय तैयार कराया था। अब लाइव स्ट्रीमिंग और नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड ने न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने विशेष रूप से कहा कि सिक्किम की तरह मध्यप्रदेश भी पूर्णतः पेपरलेस बनने की दिशा में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। इससे पर्यावरण संरक्षण को भारी संबल मिलेगा। देश के ग्रामीण व वरिष्ठजनों को ध्यान में रखते हुए तकनीक को 'बाधा' नहीं बल्कि 'पुल' बनना होगा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की एआई कमेटी, न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने पर लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय और शाहबानो प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि जब अदालतें ऐसे युगांतरकारी फैसले देती हैं, तो लोकतंत्र सशक्त होता है। आज का समय न्याय व्यवस्था, लोकतंत्र और भारतीय मूल्यों के पुनर्जागरण का काल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश न्याय और संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का प्रदेश है। यह भूमि सम्राट विक्रमादित्य और राजाभोज की परंपराओं से जुड़ी रही है। मध्य प्रदेश में "पंच परमेश्वर" की परंपरा रही है, जहाँ गाँवों में पाँच लोग बैठकर न्याय करते थे। उन्होंने आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ का उदाहरण देते हुए कहा कि महेश्वर में हुए उस ऐतिहासिक संवाद में मंडन मिश्र की पत्नी ने निष्पक्ष निर्णय देते हुए शंकराचार्य को विजयी घोषित किया था। उन्होंने कहा कि यह भारतीय न्याय परंपरा की महानता का उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार समाज और सरकार की जटिलताओं के कारण मामलों में देरी होती है। न्यायालय ऐतिहासिक फैसले देकर लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास के कठिन दौरों में भी हमारे वीरों ने विदेशी दासता के सामने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने कहा कि अनेक युद्ध जीतने के बाद भी जब आवश्यकता पड़ी, तब उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान देना स्वीकार किया। उनका साहस, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति केवल उनके समय तक सीमित नहीं रही, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रही। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नर्मदा की उज्ज्वल धारा हमारी संस्कृति, शुचिता और आध्यात्मिक चेतना को प्रदर्शित करती है। उन्होंने उपस्थित सभी अतिथियों, न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और नागरिकों का अभिनंदन किया। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने आयोजन को न्यायपालिका, सरकार और तकनीक का एक शानदार संगम बताया। उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि पहले बजट सत्रों में भारी-भरकम दस्तावेज ले जाने पड़ते थे, लेकिन आज संसद पूरी तरह पेपरलेस हो चुकी है और बजट मोबाइल पर उपलब्ध है। उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा को भी इसी दिशा में आगे बढ़ाने की उम्मीद जताते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव को अग्रिम बधाई दी। उन्होंने दुष्यंत कुमार की पंक्ति सुनाते हुए कहा कि यह 'पेपरलेस व्यवस्था' भी एक नई सोच की चिंगारी है, जो पूरी न्याय प्रणाली में उजाला फैलाएगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा ने अपने पुराने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि वर्ष 2008-09 के दौर में अदालतों में लैपटॉप ले जाने पर प्रतिबंध हुआ करता था। आज तकनीक ने पूरी व्यवस्था बदल दी है। उन्होंने बताया कि महाधिवक्ता कार्यालय की सुविधा के लिए अब उन सभी मामलों की डिजिटल पहुंच उपलब्ध करा दी गई है, जिनमें सरकार पक्षकार है।

एल.आई.सी
भारतीय जीवन बीमा से संबंधित किसी भी जानकारी या समस्या समाधान हेतु संपर्क करें।
-भारत सिंह
मो. 9967255741

महत्वपूर्ण सूचना

विज्ञापन प्रति के स्वीकृति पूर्व एहतियातन बरती जाने के बावजूद, उसमें अंतर्भूत बाते जाँचना संभव नहीं है। ऐसी अंतर्भूत बातों के लिए दैनिक स्वर्णिम प्रदेश के अंतर्गत समाचार पत्र या प्रकाशनों में आनेवाली कंपनियां, संस्थाए या व्यक्तिगत विज्ञापनों के साथ हुए किसी भी प्रकार के व्यवहार के लिए समाचार पत्र जिम्मेदार नहीं है।

मेष: नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी। कोई बड़ा कार्य हो जाने से प्रसन्नता रहेगी। निवेश लाभदायक रहेगा। भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। रोजगार में वृद्धि होगी। व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी। बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे। विवाद से बचें। आवश्यक वस्तु गुम हो सकती है।

वृषभ: व्यापार ठीक चलेगा। आय होगी। विवेक का प्रयोग करें। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। व्ययवृद्धि से तनाव रहेगा। किसी व्यक्ति के उकसावे में न आएं। विवाद से बचें। पारिवारिक चिंता बनी रहेगी। काम में मन नहीं लगेगा।

मिथुन: नए अनुबंध हो सकते हैं। रोजगार में वृद्धि होगी। रुके कार्य पूर्ण होंगे। प्रसन्नता रहेगी। नौकरी में उच्चाधिकारी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। लंबी यात्रा हो सकती है। लाभ होगा। प्रशंसा मिलेगी। घर-बाहर पूछ-परख रहेगी। प्रमाद न करें।

कर्क: व्यवसाय मनोनुकूल लाभ देगा। कार्य पूर्ण होंगे। प्रसन्नता रहेगी। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जोखिम न लें। भाइयों का सहयोग मिलेगा। आय में वृद्धि होगी। आर्थिक उन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। कोई बड़ा कार्य कर पाएंगे।

सिंह: राजकीय सहयोग से कार्य पूर्ण व लाभदायक रहेंगे। कारोबार मनोनुकूल रहेगा। शेयर मार्केट में जोखिम न लें। नौकरी में चैन रहेगा। घर-बाहर प्रसन्नता बनी रहेगी। दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं। ध्यान रखें। तीर्थदर्शन हो सकता है। सत्संग का लाभ मिलेगा।

कन्या: व्यापार ठीक चलेगा। जोखिम व जमानत के कार्य बिलकुल न करें। वाहन, मशीनरी व अग्नि आदि के प्रयोग से हानि की आशंका है, सावधानी रखें। दूसरों के झगड़ों में हस्तक्षेप न करें। आवश्यक वस्तु समय पर नहीं मिलने से क्षोभ होगा। फालतू की बातों पर ध्यान न दें।

तुला: राजकीय सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। कारोबार से लाभ होगा। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। कोई बड़ा कार्य करने की योजना बन सकती है। कार्यसिद्धि होगी। सुख के साधनों पर व्यय होगा। प्रसन्नता रहेगी। प्रमाद न करें। शत्रुओं का पराभव होगा।

वृश्चिक: प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है। भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। रोजगार में वृद्धि के योग हैं। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यस्तता रहेगी। मित्रों की सहायता कर पाएंगे। संपत्ति के बड़े सौदे बड़ा लाभ दे सकते हैं।

धनु: बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे। किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन मिल सकता है। यात्रा मनोरंजक रहेगी। पारिवारिक मांगलिक कार्य हो सकता है। नौकरी में अधिकार बढ़ सकते हैं। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। मेहनत का फल पूरा नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

मकर: आय में निश्चितता रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। लेन-देन में सावधानी रखें। किसी भी अपरिचित व्यक्ति पर अंधविश्वास न करें। शोक संदेश मिल सकता है। विवाद को बढ़ावा न दें। किसी के उकसाने में न आएं। व्यस्तता रहेगी। थकान व कमजोरी रहेगी। काम में मन नहीं लगेगा।

कुंभ: कार्यसिद्धि से प्रसन्नता रहेगी। आय में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्य करने के अवसर मिलेंगे। मेहनत सफल रहेगी। बिगड़े काम बनेंगे। घर-बाहर पूछ-परख रहेगी। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। पार्टनरों का सहयोग मिलेगा। समय की अनुकूलता का लाभ लें। धनार्जन होगा।

मीन: नए मित्र बनेंगे। अच्छी खबर मिलेगी। प्रसन्नता रहेगी। कार्यों में गति आएगी। विवेक का प्रयोग करें। लाभ में वृद्धि होगी। मित्रों के सहयोग से किसी बड़ी समस्या का हल मिलेगा। व्यापार ठीक चलेगा। घर-बाहर सुख-शांति रहेगी। पुराने संगी-साथी व रिश्तेदारों से मुलाकात होगी।

मुंबई में 5.28 करोड़ के सोने के कंगन चोरी, 3 सुरक्षाकर्मी फरार

संवाददाता

मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के कांदिवली इलाके से करोड़ों रुपये की सनसनीखेज चोरी का मामला सामने आया है। कांदिवली वेस्ट स्थित 'श्री जी मैन्युफैक्चरर्स' कंपनी के तीन सुरक्षाकर्मी कंपनी के लॉजिस्टिक्स विभाग से 3,176 ग्राम (करीब 3.1 किलो) 22 कैरेट सोने के कंगन चोरी कर फरार हो गए। चोरी गए सोने की कीमत करीब 5.28 करोड़ बताई जा रही है।

चारकोप पुलिस ने कंपनी मालिक अशोक वाया की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 306 के

पुलिस जांच में जुटी

तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, 14 मई की सुबह कंपनी मालिक को सुरक्षाकर्मी मोहम्मद अहमद का व्हाट्सऐप मैसेज मिला, जिसमें उसने वेतन न मिलने की बात कहते हुए नौकरी छोड़ने की जानकारी दी। शक होने पर जब मालिक ने फोन किया तो मोबाइल बंद मिला। इसके बाद कंपनी मैनेजर को मौके पर भेजा गया, जहां कंपनी की तीनों मंजिलों पर तैनात सभी सुरक्षाकर्मी गायब मिले।

जांच के दौरान लॉजिस्टिक्स विभाग से तैयार रखे गए करोड़ों रुपये मूल्य के सोने के कंगन भी गायब पाए गए। पुलिस के अनुसार, फरार आरोपियों की पहचान मोहम्मद सफीर उर्फ मोहम्मद अहमद (जम्मू-कश्मीर निवासी), विकास और शहबाज गुर्जर (दोनों चारकोप निवासी) के रूप में हुई है। पीड़ित अशोक वाया पिछले 45 वर्षों से ज्वेलरी निर्माण के व्यवसाय से जुड़े हैं और उनकी कंपनी में करीब 32 कर्मचारी कार्यरत हैं। पुलिस का मानना है कि पूरी चोरी की साजिश पहले से सुनियोजित थी। मामले की जांच के लिए पुलिस ने अलग-अलग टीमें गठित कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और आरोपियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है।

घोडबंदर रोड पर तेज रफ्तार का कहर: अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत

इंद्र यादव

मुंबई। ठाणे के घोडबंदर रोड पर रविवार सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक वाहन सहित फरार हो गया। मृतक युवक की पहचान सोनू सुधाकर जाधव (21) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से नासिक का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार, सोनू अपने काका केशव निंबाजी जाधव से मिलने के लिए ठाणे के पातली पाडा इलाके में आया हुआ था। जानकारी के मुताबिक, रविवार सुबह करीब 7:20 बजे सोनू अपनी मोटरसाइकिल

से पातली पाडा से घोडबंदर की ओर जा रहा था। इसी दौरान डी-मार्ट के सामने एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सोनू सड़क पर दूर जा गिरा और गंभीर चोटों के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बीट मार्शल और कासरवडवली पुलिस थाना की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पीएसआई थोरवे और उनकी टीम ने घटनास्थल का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल को सड़क किनारे हटाकर यातायात को सुचारू किया, जिससे घोडबंदर रोड पर किसी प्रकार का ट्रैफिक जाम नहीं लगा। फिलहाल कासारवडवली पुलिस अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि फरार वाहन और चालक की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके।

बढ़ती ईंधन कीमतों से गिग वर्कर्स परेशान, प्रति किलोमीटर 20 रुपये भुगतान की मांग तेज

संवाददाता

मुंबई। ईंधन की बढ़ती कीमतों ने महाराष्ट्र के लगभग 10 लाख गिग वर्कर्स की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पेट्रोल-डीजल महंगा होने के बाद ऐप आधारित डिलीवरी और परिवहन सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों ने प्रति किलोमीटर न्यूनतम 20 रुपए भुगतान की मांग तेज कर दी है। शनिवार को हुए विरोध प्रदर्शन का मुंबई और राज्य के कई हिस्सों में मिला-जुला असर देखने को मिला, जहां ब्लिंकिट जैसी क्विक डिलीवरी सेवाओं की रफ्तार धीमी पड़ गई और कई स्थानों पर डिलीवरी समय दोगुना हो गया।

यूनियनों ने चेतावनी दी है कि यदि भुगतान संरचना में जल्द सुधार नहीं किया गया तो बड़ी संख्या में गिग वर्कर्स इस सेक्टर को छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ शनिवार को देशभर में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स ने आंशिक विरोध प्रदर्शन किया। इसका असर मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में देखने को मिला, जहां फूड डिलीवरी, कैब और क्विक कॉमर्स सेवाएं प्रभावित रहीं।

गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर शनिवार दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक ऐप आधारित सेवाओं को धीमा रखने की अपील की गई थी। इसका असर ब्लिंकिट जैसी क्विक डिलीवरी सेवाओं पर भी पड़ा। जहां सामान्य दिनों में 10 से 15 मिनट में डिलीवरी होती है, वहीं कई इलाकों में डिलीवरी समय बढ़कर 25 से 30 मिनट तक पहुंच गया। गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन की अध्यक्ष सीमा सिंह ने कहा कि ऐप आधारित कर्मचारी पहले ही महंगाई से जूझ रहे हैं और अब ईंधन कीमतों में वृद्धि ने उनकी आय पर सीधा असर डाला है। उन्होंने सरकार और कंपनियों से डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 20 रुपए प्रति किलोमीटर भुगतान लागू करने की मांग की।

उनके अनुसार स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, उबर, ओला और रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े कर्मचारी सबसे अधिक प्रभावित हैं क्योंकि उनका पूरा काम दोपहिया वाहनों पर निर्भर है। यूनियन ने सरकार और ऐप आधारित कंपनियों से भुगतान संरचना में तत्काल संशोधन, सामाजिक सुरक्षा, बीमा सुविधाएं और गिग वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की है।

यूनियन पदाधिकारियों के अनुसार विरोध का असर मिला-जुला रहा, लेकिन इससे कंपनियों और सरकार तक गिग वर्कर्स की नाराजगी का स्पष्ट संदेश पहुंचा है।

महाराष्ट्र में लगभग 10 लाख गिग वर्कर्स कार्यरत हैं, जबकि देशभर में इनकी संख्या करीब 1.2 करोड़ बताई जा रही है। यूनियन का कहना है कि ईंधन कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बाद डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव और बढ़ गया है। पेट्रोल-डीजल के साथ वाहन सर्विसिंग, मेंटेनेंस और घरेलू खर्च बढ़ने के बावजूद कंपनियों ने किलोमीटर आधारित भुगतान और डिलीवरी शुल्क में कोई बड़ा संशोधन नहीं किया है।

गोरेगांव में झोपड़पट्टीवासियों के लिए विशेष समस्या समाधान शिविर आयोजित, 500 से अधिक लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान

संवाददाता

मुंबई। झोपड़पट्टी पुनर्वासन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बृहन्मुंबई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ महेन्द्र कल्याणकर के मार्गदर्शन तथा मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के सांसद रविन्द्र वायकर के सहयोग से रविवार को गोरेगांव पूर्व स्थित आरे कॉलोनी में झोपड़पट्टीवासियों की लंबित समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया। महाराष्ट्र सरकार की 'शासन आपके द्वार' अवधारणा को साकार करते हुए आयोजित इस विशेष शिविर में झोपड़पट्टीवासियों की विभिन्न समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई की गई। प्रशासन स्वयं नागरिकों के बीच पहुंचकर उनकी शिकायतें सुनता नजर आया, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों में संतोष और उम्मीद का माहौल देखने को मिला। सुबह 10 बजे से शुरू हुए इस शिविर में स्लम पुनर्वसन प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी, अभियंता, सहकार विभाग के अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पात्रता, लंबित किराया, मकानों का आवंटन, इंजीनियरिंग विभाग से जुड़ी समस्याएं तथा वर्षों

से अटकी पुनर्विकास योजनाओं को लेकर नागरिकों ने प्रशासन के समक्ष शिकायतें रखीं।कई मामलों में अधिकारियों ने मौके पर ही दस्तावेजों की जांच कर त्वरित कार्रवाई की और समस्याओं का समाधान किया। वहीं जटिल मामलों में जल्द सुनवाई और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। सांसद रविन्द्र वायकर ने शिविर में उपस्थित रहकर नागरिकों से सीधे संवाद किया। जिन लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ अथवा जिन मामलों में कार्रवाई शुरू की गई, उनका उन्होंने सम्मान भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर भारतीय को अपना घर देने का संकल्प तभी पूरा होगा जब प्रशासन संवेदनशीलता के साथ काम करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के झोपड़पट्टीवासियों को उनके ही इलाके में गुणवत्तापूर्ण आवास मिलना चाहिए।इस शिविर में अंधेरी पूर्व-पश्चिम, जोगेश्वरी पूर्व-पश्चिम, वर्सोवा, गोरेगांव पूर्व-पश्चिम और दिंडोशी क्षेत्र की 60 से अधिक सोसायटियों के लगभग 500 से अधिक झोपड़पट्टीवासी शामिल हुए। लोगों ने वर्षों से लंबित पात्रता, रुका हुआ किराया, मकानों का आवंटन, बिल्डरों की देरी और अन्य प्रशासनिक समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा।कई नागरिकों ने बताया कि वे वर्षों से कार्यालयों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था। हालांकि इस शिविर में अधिकारियों को सीधे नागरिकों के बीच आकर उनकी बातें सुनते देखकर लोगों में पहली बार यह विश्वास पैदा हुआ कि प्रशासन वास्तव में उनकी मदद के लिए आगे आया है। शिविर के दौरान कई मामलों में अधिकारियों ने संबंधित विभागों को तत्काल निर्देश देकर समस्याओं का समाधान किया, जबकि लंबित मामलों पर शीघ्र सुनवाई का भरोसा दिया। इससे झोपड़पट्टीवासियों में यह विश्वास मजबूत हुआ कि अब उनके मुद्दों का वास्तविक समाधान होगा। इस अवसर पर डॉ महेन्द्र कल्याणकर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक को उसका अधिकारपूर्ण घर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई और गरीब परिवारों को सुरक्षित, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे समस्या समाधान शिविर आगे भी विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे।उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे बिना किसी डर के अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखें और आवश्यक दस्तावेज संबंधित विभागों को सौंपें। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि झोपड़पट्टीवासियों को जल्द से जल्द घर उपलब्ध कराने और रुकी हुई योजनाओं को गति देने के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत रहेगा।

पुणे में देशी गाय केंद्र से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने की दिशा में पहल

संवाददाता

मुंबई। राहुरी के महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत पुणे कृषि महाविद्यालय में 'अजित दादा पवार देशी गाय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र' का नामकरण उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार द्वारा किया गया। अपने भाषण में उन्होंने मुख्य मुद्दों पर जोर देते हुए कहा कि सतत विकास के लक्ष्यों को सामने रखकर केंद्र को मजबूत किया जाए। उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग, सोलर पैनल से बिजली उत्पादन, स्वच्छता प्रबंधन, दुग्ध उप-उत्पादों के निर्माण और महिला किसानों को विशेष प्रशिक्षण देकर रोजगार बढ़ाने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने केंद्र में देशी गायों के वैज्ञानिक संरक्षण, नस्ल सुधार और अनुसंधान कार्य को उच्च गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए परिसर में सोलर पैनल

लगाने और गोबर के उचित प्रबंधन द्वारा स्वच्छता बनाए रखने का सुझाव दिया। साथ ही, गायों के लिए पर्याप्त चारा-पानी सुनिश्चित करने, दूध से बाय-प्रोडक्ट्स बनाने और प्रशिक्षण के जरिए ग्रामीण युवाओं व विशेषकर महिला किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर दिया, ताकि किसानों को एक नई दिशा मिल सके। इस अवसर पर तुषार पवार और कुलपति डॉ। विलास खर्चे उपस्थित थे। मुख्य वैज्ञानिक डॉ। सोमनाथ माने ने केंद्र की विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ईंधन की कमी के इस दौर में कई किसान इस केंद्र का दौरा कर रहे हैं और यहां के बायोगैस प्रोजेक्ट से प्रेरणा लेकर अपने छोटे-छोटे प्रोजेक्ट स्थापित कर रहे है। यह केंद्र किसानों, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान कर रहा है। केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों के लिए एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहा है, जिससे आधुनिक पशुपालन और टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिल रहा है।

किरीट सोमैया का BMC को पत्र, रिहायशी इलाकों में पशु वध रोकने की मांग

संवाददाता

मुंबई। बकरीद (ईद-उल-अजहा) के आगामी त्योहार को देखते हुए मुंबई में प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि उन्होंने मुंबई नगर निगम प्रशासन को पत्र लिखकर रिहायशी बस्तियों में अवैध रूप से होने वाले पशु वध को रोकने की मांग की है। सोमैया का कहना है कि नियमों के मुताबिक मुंबई की किसी भी घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके या चालों के पास पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। अपने पत्र में किरीट सोमैया ने इस बात को रेखांकित किया कि उच्च न्यायालय और नगर निगम के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद कुछ क्षेत्रों में सरेआम नियमों की धज्जियां

उड़ाई जाती हैं। उन्होंने मांग की है कि बीएमसी के सभी वार्ड अधिकारियों और स्थानीय पुलिस को त्योहार से पहले ही अलर्ट पर रखा जाए ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जा सके। किरीट सोमैया का तर्क है कि रिहायशी सोसायटियों और खुले मैदानों में पशु वध किए जाने से न केवल गंदगी फैलती है, बल्कि बच्चों और अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बीएमसी से आग्रह किया है कि केवल अधिकृत और चिन्हित कत्लखानों (Slaughterhouses) में ही कुर्बानी की अनुमति दी जानी चाहिए और अवैध रूप से पशुओं के परिवहन और वध पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। भाजपा नेता ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि मुंबई के सभी 24 वार्डों में विशेष उड़न दस्तों का गठन किया जाए। ये दस्ते इस बात की निगरानी करें कि कहीं भी सोसायटियों के भीतर अस्थायी कत्लखाने न बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि कानून का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई सांप्रदायिक सौहार्द और नागरिक व्यवस्था को बिगाड़ सकती है। मई के अंतिम सप्ताह में मनाए जाने वाले इस त्योहार को लेकर मुस्लिम समुदाय जहां अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है, वहीं किरीट सोमैया के इस पत्र ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मुंबई महानगरपालिका और पुलिस प्रशासन इस संवेदनशील मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने और नियमों का पालन करवाने के लिए क्या कदम उठाता है।

NCP में घमासान के बीच फडणवीस से मिले पार्थ पवार, बढ़ीं महा उलटफेर की अटकलें

संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति से इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दिवंगत पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के भीतर की कलह अब खुलकर सड़कों पर आ गई है। अजित पवार के जाने के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने पार्टी की कमान संभाली और खुद को सर्वेसर्वा घोषित किया है। लेकिन, हाल ही में सुनेत्रा पवार द्वारा चुनाव आयोग को भेजे गए एक पत्र ने पार्टी के भीतर बारूद का काम किया है। इस पत्र में, पार्टी के सबसे कद्दावर और वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे का नाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी से गायब मिला। उन्हें केवल एक साधारण कार्यकारिणी सदस्य के रूप में दिखाया गया। हालांकि बवाल बढ़ने पर सुनेत्रा पवार ने इसे सोशल मीडिया पर तकनीकी खराबी और पार्टी ने प्रिंटिंग मिस्टेक बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे दोनों वरिष्ठ नेताओं को किनारे

लगाने की सोची-समझी रणनीति माना जा रहा है। इस बड़े अपमान से नाराज होकर प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने सीधे अपने पुराने गुरु का रुख किया। 12 मई की रात को गुवाहाटी से लौटकर दोनों नेताओं ने बेहद गोपनीय तरीके से शरद पवार के निवास स्थान पर उनसे मुलाकात की। इस बैठक की भनक किसी को नहीं लगने दी गई। जब बारामती दौरे के दौरान शरद पवार से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने रहस्यमयी चुप्पी साध ली। वहीं, सुनील तटकरे के एक बयान ने महायुति गठबंधन में सस्पेंस और बढ़ा दिया है। तटकरे ने मीडिया से कहा, मेरा 42 वर्षों का राजनीतिक सफर है, जब मुझे बोलना होगा तो मैं बोलूंगा। भले ही वे ऊपरी तौर पर पार्टी को एनडीए (NDA) में मजबूत करने की बात कर रहे हों, लेकिन उनका यह इशारा साफ करता है कि पटेल और तटकरे अब कोई बहुत बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेने की तैयारी में हैं। पार्टी के भीतर मचे इस घमासान के बीच शनिवार की रात करीब 10 बजे एक और बड़ा मोड़ आया। अजित पवार के बेटे और सांसद पार्थ पवार अचानक अकेले ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आधिकारिक आवास वर्षा पर पहुंच गए। पार्थ पवार और प्रफुल्ल पटेल के बीच विधान परिषद चुनाव के टिकट को लेकर पहले से ही शीतयुद्ध चल रहा है। इस अत्यंत गोपनीय बैठक में किसी भी अन्य वरिष्ठ नेता का मौजूद न होना इस बात का प्रतीक है कि पार्थ पवार अब प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे की बगावत को कुचलने के लिए सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मदद की गुहार लगाने पहुंचे थे। महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में इस समय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। राकांपा के भीतर की यह कलह महायुति गठबंधन की स्थिरता को खतरे में डाल सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सुनेत्रा और पार्थ पवार अपनी पार्टी पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं, जबकि शरद पवार इस मौके का फायदा उठाकर अपने पुराने करीबियों (पटेल-तटकरे) को वापस अपने पाले में ला सकते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वर्षा पर हुई इस सीक्रेट मीटिंग के बाद महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठती है।

Odisha Vigilance Arrests Nayagarh Junior Engineer for Accepting Rs 1.36 Lakh Bribe

BHUBANESWAR: Odisha Vigilance on Saturday arrested Keshab Subudhi, Junior Engineer of Bhapur Rural Works Section in Nayagarh district, along with his associate Ashutosh Baliarsingh for allegedly demanding and accepting a bribe of Rs 1.36 lakh from a contractor.

According to Vigilance officials, the accused had demanded the bribe in exchange for clearing pending bills related to construction and maintenance work carried out under the Mukhya Mantri Sadak Yojana (MMSY) for the year 2021–22 in Khandapara area of Nayagarh district, as well as for facilitating the release of the contractor's security deposit.

Officials stated that after completion of maintenance work, the contractor had repeatedly requested the Junior Engineer over the last three to four months to take measurements and process the release of the Initial Security Deposit (ISD) and other refundable security amounts. However, the accused allegedly demanded Rs 1.36 lakh as illegal gratification for the purpose.

Following a complaint lodged by the contractor, Odisha Vigilance laid a trap on May 17 and apprehended the accused at the government residential quarters of the Junior Engineer in Khandapara while accepting the bribe amount through his associate.

Investigators said Keshab Subudhi had instructed the contractor to hand over the money to Ashutosh Baliarsingh, who was allegedly acting on his behalf. The entire bribe amount was recovered and seized in the presence of witnesses.

Subsequently, simultaneous searches were carried out at the accused officer's government residence in Khandapara, his flat at Metro Apartment in Hanspal, Bhubaneswar, and his office chamber. During the searches, officials also seized 17 old denomination currency notes of Rs 2,000 each from the government quarters. Both accused persons have been arrested and are being forwarded to court. In connection with the case, Bhubaneswar Vigilance Police Station Case No. 07 dated May 16, 2026, has been registered under Section 7 of the Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018. Further investigation is underway.

According to official records, Keshab Subudhi joined government service on February 25, 2014, as a contractual Junior Engineer in Nabarangpur RW Division-II with an initial monthly salary of Rs 9,300. He was transferred to Nayagarh RW Division in September 2020, and his services were regularised in October 2022.

Around 150 illegal shops demolished near Howrah station in anti-encroachment drive

KOLKATA: Railway authorities carried out a major anti-encroachment drive near Howrah Railway Station late Saturday night, demolishing around 150 illegal shops and temporary structures to ease passenger movement and improve security in the area, officials said. According to railway sources, several makeshift shops and unauthorised structures had been occupying space outside the station for a long time, causing inconvenience to commuters and creating congestion around the busy transport hub. A large police force was deployed during the operation and the entire area was cordoned off before bulldozers were used to remove the encroachments one by one. Officials said some shopkeepers had

removed their belongings in advance, while goods belonging to several others were affected during the demolition drive.

Railway authorities said notices had been served earlier asking the encroachers to vacate the area. However, as the encroachments remained, the administration carried out the operation following a court order. Railway Police said the drive was aimed at ensuring passenger safety and smooth movement in and around the station premises. Officials added that overcrowding and illegal occupation of public space had been causing persistent problems for commuters for a long time. While a large section of local passengers welcomed the action, some shopkeepers raised questions over the timing of the notices and the manner in which the demolition was conducted.

WORKERS DEMANDING WAGE HIKE NOT TERRORISTS, SC TELLS UTTAR PRADESH POLICE

NEW DELHI: Noting that workers protesting for a wage hike were 'not terrorists', the Supreme Court has directed the Uttar Pradesh Government to produce Aditya Anand and Rupesh Roy before the court on May 18, who were arrested in connection with last month's workers' protest in Noida. 'They are not terrorists; they are merely demanding basic rights like minimum wages,' a Bench led by Justice BV Nagarathna said,

adding that subscribing to 'leftist ideology' did not make a person a criminal. The remarks came during the hearing of a petition filed by Aditya's brother, Keshaw Anand, who has accused the Uttar Pradesh Police of subjecting the arrested men to custodial torture.

As the petitioner's counsel expressed apprehension that the two might be sent to police remand, the Bench ordered that they should continue to remain in judicial custody. After hearing lawyers representing the petitioner and the State of Uttar Pradesh, the Bench said, 'We direct respondent no. 1/State to produce the brother of the petitioner, Aditya Anand, and Rupesh Roy before this court on 18.05.2026 at 2 pm. In the meantime, judicial custody of the aforesaid two persons to continue' The Bench, also comprising Justice Ujjal Bhuyan, issued notice to the State of Uttar Pradesh and directed the production of the two men. It posted the matter for further hearing at 2 pm on May 18. Aditya Anand, a software engineer and social worker, and Rupesh Roy, an auto driver, had participated in the protest demanding higher minimum wages and decent working hours for workers, the petitioner submitted. Keshaw alleged that Aditya was arrested on April 17 at Tiruchirappalli railway station in Tamil Nadu without being informed of the grounds of arrest and without being provided an arrest memo. He alleged that Aditya was not allowed to inform his family or legal counsel about the arrest despite several representations to authorities in Tamil Nadu and Uttar Pradesh regarding his detention.

Aditya was later brought to Uttar Pradesh, where he was arrested under various provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, the petitioner alleged. Rupesh, the petitioner alleged, was picked up by the police from Botanical Garden Metro Station and subjected to severe torture, following which the police made a fake disclosure and recovery to implicate him.

तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही गुजरात देशाचे नेतृत्व करेल - अमित शहा

गांधीनगर। केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी रविवारी अहमदाबाद येथे 'मिलियन माइंड्स टेक पार्क' तसेच 'गणेश रियल इस्टेट मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट'चे लोकार्पण करताना सांगितले की, ज्या प्रकारे गुजरातने स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून देशाला दिशा दिली आहे, त्याचप्रमाणे आता तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष क्षेत्रातही गुजरात संपूर्ण देशाचे नेतृत्व करेल.

अमित शाह म्हणाले की, गुजराती लोकांच्या स्वभावात विकास आणि प्रगती रुजलेली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गुजरात आता केवळ उत्पादनाधारित राज्य राहणार नाही, तर सेवा, ज्ञान आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेचे जागतिक केंद्र बनेल. आज लोकार्पण करण्यात आलेले हे दोन्ही प्रकल्प राज्यातील युवकांना नवी संधी उपलब्ध करून देतील आणि गुजरातला नव्या उंचीवर नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, अहमदाबाद-गांधीनगर उच्च विकास पट्ट्यात सुमारे ६५ एकर क्षेत्रात हे तंत्रज्ञान नगर विकसित करण्यात येत आहे. येथे अत्याधुनिक कार्यालये, निवासी सुविधा, व्यावसायिक संकुले तसेच आतिथ्य सेवांशी संबंधित विविध सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. या प्रकल्पामुळे ७० हजारांहून अधिक युवकांना उच्च कौशल्याधारित रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स तंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टर उत्पादन निर्मिती तसेच आधुनिक संशोधन यांसारख्या क्षेत्रांत गुजरात वेगाने प्रगती करत आहे. हा प्रकल्प राज्यातील नवे तंत्रज्ञान, संशोधन आणि नवोन्मेष यांना भक्कम आधार देईल. येत्या काळात गुजरात सेवा क्षेत्रात देशातील अग्रगण्य राज्यांमध्ये समाविष्ट होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

'गणेश रियल इस्टेट मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट'चा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, आधुनिक शहरी विकास आणि बांधकाम क्षेत्रासाठी ही संस्था महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. येथे नव्या तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणासह जागतिक दर्जाच्या मानकांनुसार प्रशिक्षण दिले जाईल, ज्यामुळे कुशल मनुष्यबळ तयार होईल.

यावेळी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी सांगितले की, गुजरात आता ज्ञान, नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञानाधारित विकासाच्या दिशेने वेगाने पुढे जात आहे. तर राज्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी सांगितले की, येणारा काळ गुजरातचा असून राज्य जागतिक गुंतवणूक आणि आधुनिक उद्योगांचे प्रमुख केंद्र बनणार आहे. या कार्यक्रमाला अनेक उद्योगपती, गुंतवणूकदार आणि मान्यवर नागरिक उपस्थित होते.

भारत-बांग्लादेश सीमेवर काटेरी तार लावण्यासाठी जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेला सुरुवात

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकारच्या निर्देशानंतर मालदा जिल्ह्यात भारत-बांग्लादेशच्या खुल्या सीमेवर काटेरी तार लावण्यासाठी जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. शनिवारी हबीबपूर ब्लॉकमधील भवानीपूर आणि आग्रा हरिश्चंद्रपूर परिसरात भूमी व भूमी सुधार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सीमावर्ती भागातील जमिनीच्या कागदपत्रांची तपासणी करत मोजमापाचे काम सुरू केले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मालदा जिल्ह्यातील सहा पोलीस ठाणे क्षेत्रांमध्ये भारत-बांग्लादेश सीमेची एकूण लांबी सुमारे १७२ किलोमीटर आहे. यापैकी जवळपास ३३ किलोमीटर सीमा अद्याप खुली आहे. सर्वाधिक खुली सीमा हबीबपूर ब्लॉकमध्ये असून, येथे २० ते २५ किलोमीटर परिसरात अद्याप काटेरी तार लावण्यात आलेली नाही.

जिल्ह्यात सीमा सुरक्षेसाठी काटेरी तार उभारण्यासाठी सुमारे २६० एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. प्रशासकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत १० एकर जमीन अधिग्रहणाचे काम पूर्ण झाले आहे. शुक्रवारी मालदा जिल्हाधिकारी कार्यालयात सीमा सुरक्षा दल आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात या विषयावर आपत्कालीन बैठकही झाली होती. त्यानंतर भूमी व भूमी सुधार विभागाने जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेला गती दिली. सीमावर्ती शेतकऱ्यांनी प्रशासनाच्या या उपक्रमाचे स्वागत केले आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, यापूर्वी तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या काळात अनेकदा जमीन अधिग्रहणाच्या नावाखाली मोजमाप करण्यात आले, मात्र प्रत्यक्ष काम पुढे सरकले नाही. शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, सीमा खुली असल्यामुळे बांग्लादेशी

गुन्हेगारांकडून पिकांची लूटमार होत होती. त्यांचे मत आहे की, काटेरी तार उभारल्यानंतर अशा घटनांना आळा बसेल. हबीबपूर ब्लॉकचे भूमी व भूमी सुधार अधिकारी स्वपन तरफदार यांनी सांगितले की, विभागीय कर्मचारी शेतकऱ्यांकडून जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे गोळा करत असून जमिनीचे मोजमाप सुरू झाले आहे. निर्धारित कालमर्यादेत अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

या मुद्द्यावर जुएल मुर्मू यांनी आरोप केला की, तृणमूल सरकारच्या कार्यकाळात सीमेवर काटेरी तार उभारण्यात अडथळे निर्माण करण्यात आले होते. त्यांनी म्हटले की, मतबँकेच्या राजकारणामुळे त्या वेळी या प्रकल्पाला पुढे जाऊ दिले गेले नाही. आता पश्चिम बंगालमध्ये भाजप सरकार आल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देत जमीन अधिग्रहणाचे काम सुरू करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला.

होर्मुझमध्ये आमच्या जहाजांवरील हल्ले अस्वीकार्य, भारताने संयुक्त राष्ट्रांसमोर मांडली बाजू

न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी, पी. हरीश यांनी पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा आणि खतांच्या संकटावर भारताचा दृष्टिकोन मांडला. त्यांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सागरी सुरक्षा आणि नौकानयनाच्या स्वातंत्र्यात होणाऱ्या व्यत्ययाबद्दल चिंता व्यक्त केली. हरीश यांनी व्यापारी जहाजांना लक्ष्य करणे आणि नागरी कर्मचाऱ्यांचा जीव धोक्यात घालणे अस्वीकार्य असल्याचे म्हटले. भारताने यावरही जोर दिला की सुरक्षित सागरी मार्गांसंबंधीच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पूर्णपणे पालन केले पाहिजे.

पी. हरीश यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेच्या विशेष बैठकीत भाग घेतला. ऊर्जा आणि पुरवठा प्रवाहांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा या बैठकीचा उद्देश होता. त्यांनी सांगितले की या संकटाचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी अल्पकालीन आणि संरचनात्मक उपाययोजना आवश्यक आहेत. आंतरराष्ट्रीय सहकार्य देखील

महत्त्वाची भूमिका बजावेल. हरीश यांनी लिहिले की आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा पूर्णपणे आदर केला पाहिजे. इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सागरी वाहतुकीचे नियमन करण्यासाठी एका व्यावसायिक यंत्रणेची घोषणा केली आहे. इराणच्या संसदेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे प्रमुख इब्राहिम अझीझी यांनी सांगितले की, ही यंत्रणा लवकरच सादर केली जाईल. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने, इराणच्या राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाखाली ती विकसित करण्यात आली आहे. या यंत्रणेचा फायदा केवळ इराणसोबत सहकार्य करणाऱ्या व्यापारी जहाजांनाच होईल. 'फ्रीडम प्रोजेक्ट'शी संबंधित ऑपरेटर्ससाठी हा मार्ग बंद राहील.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इशारा दिला आहे की, पश्चिम आशियातील संकट संपवण्यासाठी शांतता करार न झाल्यास अंधारमय काळ येईल.

दरम्यान, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची म्हणाले की, पश्चिम आशियातील शांततेच्या मार्गातील अमेरिका हा मुख्य अडथळा आहे. अराघची यांनी दावा केला की, ४० दिवसांच्या युद्धानंतर अमेरिकेने चर्चेचा प्रस्ताव दिला आहे. ते म्हणाले की, या हालचालीबद्दल तेहरानमध्ये तीव्र संशय आहे. अराघची यांनी अमेरिकेवर अविश्वास व्यक्त केला आणि त्यांना कोणत्याही राजनैतिक प्रयत्नांमधील मुख्य अडथळा म्हटले.

खरं तर, काही दिवसांपूर्वी ओमानच्या किनाऱ्याजवळ भारतीय ध्वज असलेल्या एका व्यापारी जहाजावर हल्ला झाला होता. हे जहाज सोमालियाहून निघाले होते. ओमानच्या अधिकाऱ्यांनी जहाजावरील सर्व १४ कर्मचाऱ्यांची सुटका केली, परंतु हल्लेखोराची ओळख अद्याप निश्चित झालेली नाही.

आलिया के सपोर्ट में उतरे सोनू सूद, ट्रोलर्स को दिया जवाब

मुंबई। अभिनेत्री आलिया भट्ट इन दिनो कांस फिल्म फेस्टिवल में कथित तौर पर फोटोग्राफर के द्वारा नरअंदाज किए जाने पर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना कर रही है। इसी, बीच शुक्रवार को अभिनेता सोनू सूद आलिया के सपोर्ट पर सामने आए। अभिनेता ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर आलिया के लिए नोट शेयर किया। इसके जरिए उन्होंने कहा कि किसी भी कलाकार की मेहनत और वैश्विक उपलब्धि को सिर्फ कैमरों की चमक से नहीं आंका जा सकता है। अभिनेता ने ट्रोलर्स को फटकार लगाते हुए नोट पर लिखा, 'जब हमारा ही कोई अपना व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कदम रखता है, तो यह हमारे लिए गर्व का पल होना चाहिए, न कि कमियां ढूंढने का बहाना। हर उपलब्धि को सार्थक होने के लिए कैमरों, सुर्खियों या अजनबियों से

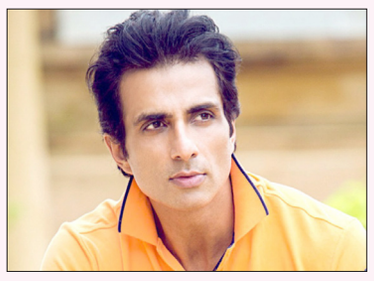

मान्यता मिलने की जरूरत नहीं होती।'

उन्होंने आलिया के अंतरराष्ट्रीय दौरे का सम्मान करते हुए लिखा, 'अंतरराष्ट्रीय स्टेज पर खड़े होना, अपनी कला का प्रतिनिधित्व करना और अपनी यात्रा को गरिमा के साथ आगे बढ़ाने का साहस ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है।'

सोनू ने आगे लिखा, 'आज की दुनिया को ट्रोलिंग की लत लग चुकी है, लेकिन हमें प्रोत्साहन को चुनना चाहिए। याद रखें जो लोग अपने सपने बुनने में व्यस्त होते हैं, उनके पास दूसरों को नीचे खींचने के लिए वक्त नहीं होता।' उन्होंने आखिरी में लिखा, 'हमें तुम पर गर्व है, मेरे दोस्त। सही लोगों ने तुम्हारी चमक को पहचान लिया।' हालांकि, अपनी इस पोस्ट में सोनू ने साफ तौर पर आलिया का नाम नहीं लिखा लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर आलिया के लिए ही था क्योंकि अभी आलिया को सोशल मीडिया पर कांस दौरे पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

बता दें कि रेड कार्पेट पर उनके वीडियो को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। जहां कुछ लोगों ने उनके कॉन्फिडेंस और एलिगेंट लुक की तारीफ की, वहीं कुछ ट्रोलर्स ने उन्हें विदेशी पैपराजी द्वारा कम अटेंशन मिलने को लेकर आलोचना भी की।

महिलाएं आज भी बराबरी के लिए लड़ रही हैं - सबा आजाद

मुंबई। अभिनेत्री सबा आजाद जल्द ही कॉमेडी-ड्रामा सीरीज 'हूज योर गायनिक सीजन 2' में नजर आएंगी। इस सीरीज में वे 'डॉ. विदुषी कोठारी' की भूमिका निभाती नजर आएंगी। आगामी सीजन को लेकर अभिनेत्री का कहना है कि सीरीज का मुख्य उद्देश्य उन विषयों पर चर्चा करना है, जिन्हें अक्सर बंद कमरों की चर्चा माना जाता है। उन्होंने आईएएनएस के साथ बातचीत में बताया, 'सीजन-1 ने सेक्स एजुकेशन और महिलाओं के स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद शुरू किया था। सीजन-2 भी उसी मूल विचार को कायम रखेगा। समाज इन चर्चाओं को जगह मिलना बहुत जरूरी है।' 'आज के समय में भी समाज के लिए एक स्वतंत्र और महत्वकांक्षी महिला को स्वीकार करना कठिन है?' इस

पर अभिनेत्री का कहना है कि भले ही हम बड़े शहरों में रहते हों, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी पितृसत्तात्मक है। उन्होंने कहा, 'महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान पाने के लिए आज भी दोगुना मेहनत करनी पड़ती है। समाज आज भी महिलाओं के फैसलों पर बहुत जल्द अपनी राय बना लेते हैं। हमारा सामाजिक ढांचा पारंपरिक रूप से पुरुषों की सफलता को केंद्र में रखकर बनाया गया है।' उन्होंने आगे लिखा, 'हमारे देश के कई हिस्सों में महिलाओं को आज भी आजादी से काम करने या अपने फैसले खुद लेने की अनुमति नहीं है। हो सकता है कि शहरों में हमें यह सच्चाई हमेशा दिखाई न दे, लेकिन यह मौजूद है। इसलिए महिलाओं को पेशेवर और घर दोनों जगह लगातार खुद को साबित करना पड़ता है। अगर वे काम करती हैं, तो लोग उन पर उंगलियां उठाते हैं। अगर वे काम नहीं करतीं, तो उन्हें फिर से परखा जाता है।' सबा का मानना है कि कुछ लड़कों की परवरिश अक्सर इसी मानसिकता के साथ की जाती है कि वे महिलाओं से बेहतर हैं। ऐसे में जब उनका सामना एक सशक्त और स्वतंत्र विचार वाली लड़की से होता है, तो उनके अहंकार को ठेस पहुंचती है। उन्होंने कहा, 'सच बात तो ये है कि ऐसे पुरुषों को महिलाओं को अपने से बराबर देखने की आदत नहीं होती, जिससे रिश्तों में तनाव पैदा होता है।'

महवश ने समाज की सोच पर उठाए सवाल

मुंबई। अभिनेत्री महवश अपनी आगामी वेब सीरीज 'सतरंगीः बदले का खेल' की रिलीज को लेकर तैयार हैं। अभिनेत्री का कहना है कि इस सीरीज में उत्तर भारत की लोक कला 'लौंडा नाच' और जाति-आधारित भेदभाव जैसे गंभीर मुद्दों को भी उठाया है। अभिनेत्री ने आईएएनएस के साथ बातचीत में बताया कि स्क्रिप्ट सुनते ही उन्होंने इसके लिए तुरंत हामी भर दी थी। उन्होंने कहा, 'जब मैंने कहानी सुनी, तो मुझे लगा कि यह सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक सामाजिक संदेश देने का माध्यम भी है। उत्तर प्रदेश में पली-बढ़ी होने के नाते मैंने अपने आस-पास ऐसी सच्चाइयों को देखा और सुना था। उस दुनिया का हिस्सा बनना मेरे लिए एक बहुत ही सार्थक मौका था। मेरे किरदार में भी कई इमोशनल परतें हैं और एक एक्टर के लिए, ऐसी जटिलता हमेशा रोमांचक होती है।' सीरीज के ट्रेलर से साफ पता चलता है कि इसकी कहानी बदले की नहीं, बल्कि पहचान और आत्म-सम्मान की लड़ाई भी है। अभिनेत्री ने बताया कि आज भी समाज में काफी लोगों को उनके टाइटल से जज किया जाता है। जाति आधारित हिंसा आज भी हमारे आसपास देखने को मिलती है। हम सीरीज के माध्यम से बस यह दिखाना चाहते थे कि इंसान का जिन बातों पर बस नहीं होता, उनकी वजह से लोगों को किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। यह यकीनन पहचान और इंसाफ की लड़ाई है और मुझे उम्मीद है कि आखिर में समाज यह लड़ाई जीत जाएगा। महवश ने सीरीज में एक ऐसे प्रभावशाली और बाहुबली परिवार की ग्रामीण लड़की का किरदार निभाया है, जो अपने ही परिवार द्वारा किए जा रहे अत्याचारों और जाति व्यवस्था के खिलाफ खड़ी होती है। अपने ग्रामीण किरदार को लेकर अभिनेत्री का कहना है कि उनके लिए यह मुश्किल नहीं था।

अक्सर हम फल खाने के बाद उनके बीजों को बेकार समझकर फेंक देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि खरबूजे के छोटे-छोटे बीज सेहत का एक बड़ा खजाना अपने भीतर समेटे हुए हैं। अपने दैनिक डाइट में छोटे-छोटे बदलाव करना भविष्य में बड़े और सकारात्मक परिणाम दे सकता है। इसी कड़ी में पोषक तत्वों से भरपूर खरबूजे के बीजों को शामिल करने की पुरजोर सलाह दी जाती है क्योंकि इनके सेवन से शरीर को एक नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं।

प्रोटीन और फाइबर से भरपूर खरबूजे के बीज क्यों हैं सुपरफूड?

पोषक तत्वों का भंडार है यह बीज

खरबूजे के बीजों में मुख्य रूप से प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और विभिन्न खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यही कारण है कि इन्हें सेहत के लिए प्राकृतिक खजाना माना गया है। इनमें मौजूद प्रोटीन की प्रचुर मात्रा शरीर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होती है जो इसे जिम जाने वालों और शारीरिक मेहनत करने वालों के लिए एक सस्ता और सुलभ विकल्प बनाती है।

ब्लड प्रेशर और इम्युनिटी में सुधार

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हाई ब्लड प्रेशर एक गंभीर समस्या बन चुकी है। खरबूजे के बीज शरीर में सोडियम के स्तर को प्रभावी ढंग से संतुलित रखते हैं जिससे ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखने में बड़ी मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त ये बीज शरीर की रक्षा प्रणाली यानी इम्युनिटी

को भी अभूतपूर्व रूप से मजबूत करते हैं। नियमित सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि सर्दी-जुकाम जैसी आम बीमारियाँ शरीर को आसानी से प्रभावित नहीं कर पाती।

पाचन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए वरदान

पाचन संबंधी समस्याओं विशेष रूप से कब्ज से जूझ रहे लोगों के लिए खरबूजे के बीज किसी औषधि से कम नहीं हैं। फाइबर से भरपूर होने के कारण ये पाचन तंत्र को सुचारू बनाते हैं और पेट को साफ रखने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं यह सुपरफूड आपके मस्तिष्क के लिए भी उतना ही प्रभावी है। इसके नियमित सेवन से स्मरण शक्ति तेज होती है और एकाग्रता बढ़ती है। सौंदर्य के लिहाज से देखें तो इनमें मौजूद पोषक तत्व बालों को जड़ों से मजबूत बनाते हैं और नाखूनों की सेहत में भी सुधार करते हैं।

कैसे करें डाइट में शामिल?

खरबूजे के बीजों को आहार का हिस्सा बनाना बेहद सरल है। आप इन्हें हल्का भूनकर नमक या स्वादानुसार मसालों के साथ एक स्वास्थ्यवर्धक स्नैक के रूप में खा सकते हैं। इसके अलावा इन्हें सलाद, दही या सुबह के नाश्ते में ऊपर से छिड़क कर इस्तेमाल किया जा सकता है। कई लोग इन्हें चाय या दूध के साथ मिलाकर भी सेवन करना पसंद करते हैं जिससे उनके पोषण का स्तर और बढ़ जाता है।

बिना किसी दुष्प्रभाव के स्वास्थ्य सुधारने का यह सबसे सस्ता और प्राकृतिक तरीका है। यदि आप अपनी जीवनशैली को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो आज से ही इस बहुमुखी सुपरफूड को अपनी थाली में जगह दें।

बालासन से शवासन तक: शाम के योग से मिलेगा सुकून और ऊर्जा

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में काम का दबाव, मानसिक थकान और निरंतर भाग-दौड़ हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में अक्सर लोग शारीरिक और मानसिक रूप से टूट जाते हैं। लेकिन अगर आप शाम के समय केवल 15 से 20 मिनट का समय खुद के लिए निकालें तो पूरे दिन की थकान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। योग न केवल शरीर को लचीला बनाता है बल्कि यह मानसिक शांति प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

शाम का योग क्यों है जरूरी

नियमित रूप से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने फायदेमंद होता है। शाम के समय किया जाने वाला योग शरीर को धीरे-धीरे आराम की स्थिति में लाने का काम करता है। इससे न केवल मांसपेशियों का तनाव कम होता है बल्कि दिमाग भी शांत होता है जिससे रात में अच्छी और गहरी नींद आने की संभावना काफी बढ़ जाती है। यदि इसे रोजाना सही तरीके से किया जाए तो सकारात्मक परिणाम कुछ ही दिनों में दिखने लगते हैं।

तनाव और थकान कम

शाम के योग में कुछ विशेष आसनों को शामिल करना अत्यंत लाभकारी हो सकता है। जिससे आपको रात के समय अच्छी नींद भी आएगी और दिनभर की थकान भी गायब हो जाएगी।

बालासन और मार्जरीआसन

बालासन उन लोगों के लिए वरदान है जो पूरे दिन डेस्क जॉब करते हैं या मानसिक तनाव

से जूझते हैं। यह आसन नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और पीठ व कंधों की जकड़न को दूर करता है। वहीं मार्जरीआसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और शरीर में रक्त संचार को बेहतर करता है जिससे दिनभर की अकड़न कम होती है।

पश्चिमोत्तानासन और विपरीत करणी

पश्चिमोत्तानासन पूरे शरीर को स्ट्रेच करता है जिससे रीढ़ और पैरों की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। यह पाचन क्रिया में सुधार करने के साथ-साथ चिंताओं पर नियंत्रण पाने में भी सहायक है। इसके अतिरिक्त विपरीत करणी उन लोगों के लिए प्रभावी है जो लंबे समय तक खड़े रहते हैं या चलते हैं। यह पैरों की थकान मिटाता है और विशेष रूप से अनिद्रा की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए लाभकारी है।

शवासन

किसी भी योग सत्र का समापन शवासन के बिना अधूरा माना जाता है। इस आसन में शरीर को पूरी तरह स्थिर रखा जाता है और ध्यान केवल सांसों पर केंद्रित होता है। यह शरीर और मन दोनों को गहरी शांति प्रदान करता है जिससे मानसिक संतुलन बना रहता है और दिनभर की सारी थकान दूर हो जाती है। शाम का 20 मिनट का यह लघु योग सत्र आपके स्वास्थ्य के लिए एक निवेश की तरह है। संतुलित रक्त संचार, बेहतर पाचन और शांत मन के माध्यम से आप न केवल तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं बल्कि अपनी कार्यक्षमता में भी सुधार कर सकते हैं।

पिंपल्स और झुर्रियों में मदद करेगा केले का छिलका

अक्सर हम केला खाने के बाद उसके छिलके को बेकार समझकर फेंक देते हैं लेकिन स्किन एक्सपर्ट्स इसे एक सुपरफूड मानते हैं। विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर केले का छिलका न केवल आपकी त्वचा को गहराई से मॉइश्चराइज करता है बल्कि यह एक्ने और समय से पहले आने वाली झुर्रियों का भी काल है।

डिजिटल दौर में जहां लोग महंगे स्किन केयर रूटीन के पीछे भाग रहे हैं वहीं आपके किचन में मौजूद केले का छिलका एक नेचुरल ब्यूटी डॉक्टर की तरह काम करता है। इसमें मौजूद पोटेशियम, विटामिन और प्राकृतिक तेल आपकी त्वचा के टेक्सचर में सुधार लाते हैं और उसे अंदर से पोषण देते हैं।

पिंपल्स और दाग-धब्बों

यदि आप बार-बार होने वाले पिंपल्स से परेशान हैं तो केले का छिलका आपके काम आ सकता है। इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण चेहरे की सूजन को कम करते हैं और बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। छिलके के अंदरूनी हिस्से को प्रभावित जगह पर रगड़ने से कुछ ही दिनों में चेहरे पर निखार आने लगता है।

एंटी-एजिंग

बढ़ती उम्र के लक्षणों को रोकने के लिए केले का छिलका बेहद असरदार है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं जिससे चेहरे की महीन रेखाएं और झुर्रियां कम होने लगती हैं। यह त्वचा में कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देता है जिससे आपकी स्किन अधिक टाइट और जवां नजर आती है।

नेचुरल मॉइश्चराइजर और ग्लोइंग स्किन

रूखी त्वचा वालों के लिए यह किसी जादुई नुस्खे जैसा है। केले के छिलके में मौजूद फैटी एसिड्स त्वचा की नमी को लॉक करते हैं। अगर आप डार्क स्पॉट्स या हाइपरपिग्मेंटेशन से परेशान हैं तो नियमित रूप से छिलके का इस्तेमाल आपके कॉम्प्लेक्शन को एक समान बनाता है और चेहरे पर एक नेचुरल चमक लाता है।

इस्तेमाल का सही तरीका

सबसे पहले अपना चेहरा धोकर सुखा लें। अब केले के छिलके के सफेद वाले हिस्से को चेहरे पर हल्के हाथों से तब तक रगड़ें जब तक कि छिलका भूरा न हो जाए। इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें। बेहतरीन परिणामों के लिए सप्ताह में कम से कम तीन बार इसे दोहराएं।

राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग

68 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, रेल यातायात प्रभावित

संवाददाता

रतलाम। केरल के तिरुवनंतपुरम से हजरत निजामुद्दीन (दिल्ली) जा रही राजधानी एक्सप्रेस में रविवार तड़के अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। घटना मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट क्षेत्र में लूणी रीछा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के बीच हुई। आग ट्रेन के एसी कोच बी-1 में लगी, जिसमें उस समय 68 यात्री सवार थे। घटना सुबह करीब 5:15 से 5:30 बजे के बीच की बताई जा रही है। ट्रेन संख्या 12431 त्रिवेंद्रम-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस रतलाम जंक्शन से रात लगभग 3:45 बजे रवाना हुई और उसका अगला ठहराव कोटा जंक्शन था, लेकिन राजस्थान में प्रवेश करने से पहले ही ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें सक्रिय हो गईं। रतलाम कंट्रोल रूम को सुबह 5:20 बजे कोटा कंट्रोल से हादसे की सूचना मिली। इसके बाद रतलाम से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन (एआरटी), मेडिकल रिलीफ इकाई (एआरएमई) और टावर वैगन को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। रतलाम रेल मंडल के डीआरएम अश्विनी कुमार भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौके के लिए रवाना हो गए। राहत और बचाव कार्य के दौरान रेलवे कर्मचारियों ने प्रभावित कोच का बिजली कनेक्शन काट दिया और उसे ट्रेन से अलग कर दिया, ताकि आग अन्य डिब्बों तक न फैल सके। इसका असर देश

के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में शामिल दिल्ली-मुंबई ट्रैक पर भी पड़ा। सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए रेल यातायात रोकना पड़ा, जिससे कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। मुंबई सेंट्रल-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर रोका गया। रेलवे प्रशासन ने बताया कि ट्रैक को जल्द बहाल करने की कोशिश की गई और स्थिति सामान्य करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। रेलवे प्रशासन ने प्रभावित यात्रियों के लिए तत्काल राहत व्यवस्था भी शुरू की। बी-1 कोच में सफर कर रहे यात्रियों के लिए नाश्ते और पेयजल की व्यवस्था की गई। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों को अन्य कोचों में समायोजित कर कोटा तक पहुंचाया जाएगा। वहां से एक अतिरिक्त कोच जोड़कर यात्रियों को आगे दिल्ली तक भेजने की व्यवस्था की जा रही है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देने की बात कही है। घटना के कारणों को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रेलवे अधिकारियों ने प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई है। सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि आग लगने के वास्तविक कारणों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल तकनीकी टीम यह पता लगाने में जुटी है कि आग इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से लगी या किसी अन्य वजह से हादसा हुआ। रेलवे प्रशासन ने प्रभावित कोच और उसमें रखे सामान के नुकसान का भी आकलन शुरू कर दिया है। ट्रेन में मौजूद यात्रियों के बीच कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया। कई यात्रियों ने बताया कि अचानक धुआं भरने लगा और लोग घबराकर बाहर निकलने लगे। हालांकि रेलवे स्टाफ की तत्परता के कारण स्थिति जल्द नियंत्रण में आ गई। यात्रियों ने रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता और रेस्क्यू टीम की तेजी की सराहना की। उनका कहना था कि यदि कुछ मिनट की भी देरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि ट्रेन संख्या 12431 के बी-1 कोच में आग लगने की सूचना सुबह 5:20 बजे प्राप्त हुई थी। घटना लूणीरिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के मध्य हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। राहत और बचाव कार्य समय पर शुरू कर दिया गया था और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं, रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, सबसे पहले ट्रेन के गार्ड ने बी-1 कोच से धुआं और आग की लपटें उठती देखीं। उन्होंने तत्काल लोको पायलट को सूचना दी, जिसके बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को तुरंत रोका गया। इसके बाद रेलवे कर्मचारियों और स्टाफ ने तेजी से कार्रवाई करते हुए करीब 15 मिनट के भीतर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यात्रियों को दूसरे डिब्बों में शिफ्ट किया गया। समय रहते रेस्क्यू होने के कारण किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, पर आग की चपेट में आने से कोच को भारी नुकसान पहुंचा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दो डिब्बे प्रभावित हुए हैं।

होशियारपुर में 'पीआईए' लिखा हॉट बैलून मिला

संवाददाता

चंडीगढ़। पंजाब के होशियारपुर में रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब दसूहा सडक़ पर स्थित गांव सतौर के बाहरी क्षेत्र में खेतों में एक छोटी हवाई जहाज जैसी दिखने वाली संदिग्ध वस्तु पड़ी मिली। इस पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन लिखा हुआ था। दूर से देखने पर यह वस्तु एक ड्रोन जैसी लग रही थी। खेतों की ओर जा रहे कुछ ग्रामीणों ने इस वस्तु को देखा और तुरंत गांव की सरपंच कुलदीप कौर और समिति सदस्य परमजीत सिंह को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस के अनुसार

वह वस्तु असल में एक हॉट एयर बैलून थी, जिसका आकार हवाई जहाज जैसा था और उस पर 'पीआईए' लिखा हुआ था। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि यह बैलून कहां से आया और क्या इस इलाके में कोई सामग्री गिराई गई है। आसपास के खेतों और नजदीकी इलाकों में तलाशी अभियान भी चलाया, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला।

भगवान रुद्रनाथ की देव डोली हिमालय के लिए रवाना

संवाददाता

देहरादून। चमोली जनपद में स्थित पंच केदारों में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली रविवार को अपने शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर, गोपेश्वर से मध्य हिमालय स्थित रुद्रनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गई। मंदिर के मुख्य पुजारी हरीश भट्ट ने बताया कि रुद्रनाथ मंदिर के कपाट सोमवार 18 मई को मध्याह्न में परंपरानुसार एवं वैदिक विधि-विधान के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोले जाएंगे। कपाट खुलने के बाद श्रद्धालु भगवान रुद्रनाथ के एकानन स्वरूप के दर्शन एवं पूजा-अर्चना कर सकेंगे।

कपाट खुलने की प्रक्रिया के तहत गोपीनाथ मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की गई। पूजा के बाद भगवान रुद्रनाथ की देव डोली जयकारों, पुष्प वर्षा और सेना के बैंड की मधुर धुनों के बीच श्रद्धालुओं के साथ मंदिर के लिए प्रस्थान कर गई। इस अवसर

पर चमोली के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, थराली विधायक भूपाल राम, राज्यमंत्री हरक सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट, नगरपालिका अध्यक्ष संदीप रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल बर्तवाल, महामंत्री अरुण मैठाणी, विनोद कनवासी, मंदिर समिति अध्यक्ष मनोज भट्ट, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार सहित बड़ी संख्या ओं श्रद्धालु उपस्थित थे।

मप्र सरकार का बड़ा फैसला: हर स्नातक पाठ्यक्रम में शहीदों की पत्नी एवं बच्चों के लिए अब एक सीट रहेगी आरक्षित

संवाददाता

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने शहीदों के परिजनों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के परिपालन में उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में पुलिस, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) में शहीद होने वाले कर्मियों की विधवाओं तथा उनके आश्रित बच्चों के लिए एक अतिरिक्त सीट आरक्षित की है।

इस संबंध में उच्च शिक्षा आयुक्त प्रबल सिपाहा ने शनिवार को सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को निर्देश जारी कर दिए हैं। विभागीय निर्देशानुसार प्रत्येक स्नातक पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त एक सुपरन्यूमेरेरी (अतिरिक्त) सीट

निर्धारित की गई है, इससे नियमित सीटों की संख्या प्रभावित नहीं होगी। इस आरक्षण का लाभ केवल पात्र अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी(गृह विभाग अथवा संबंधित विभाग) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगा। पात्र अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर पृथक श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करना होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों और सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को लिखे पत्र में कहा है कि प्रवेश मार्गदर्शिका 2026-27 में एक अतिरिक्त सीट का आरक्षण करना अनिवार्य है। यह अतिरिक्त सीट प्रदेश के सभी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में आरक्षित रखी जाएगी। इसमें पुलिस, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) के शहीदों की विधवा और उनके आश्रित बच्चों के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। उच्च शिक्षा आयुक्त ने कहा है कि हर स्नातक पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीट के अलावा एक सीट सुपर न्यूमेरेरी सीट बनाई गई है। यह सीट नियमित सीट्स की संख्या को प्रभावित नहीं करेगी यानी प्रवेश के लिए जितनी सीट्स पहले से तय हैं उनकी संख्या में कोई कमी नहीं होगी।

जनपद में सैनिक स्कूल की 11वीं लोकल बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बैठक संपन्न, NDA चयनित कैडेट रघुवेंद्र प्रताप सिंह सम्मानित

संवाददाता

झांसी, उत्तर प्रदेश। सैनिक स्कूल झांसी की 11वीं लोकल बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (LBA) बैठक शनिवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मेजर जनरल मनदीप सिंह, एवीएसएम, एसएम, अध्यक्ष LBA एवं जनरल ऑफिसर कमांडिंग, 31 आर्मर्ड डिवीजन ने की।इस उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न प्रमुख विभागों और संस्थानों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की।

बैठक में सांसद प्रतिनिधि, लोक निर्माण विभाग (PWD), उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (UPRNNL), नवोदय विद्यालय समिति (NVS) तथा आर्मी पब्लिक

स्कूल (APS) के प्रतिनिधि मौजूद रहे।बैठक के दौरान सैनिक स्कूल झांसी के शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं आधारभूत संरचना विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बोर्ड ने विद्यालय के समग्र विकास और अधोसंरचना को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने के लिए रणनीतिक योजनाओं पर विचार-विमर्श किया। अधिकारियों ने कैडेट्स के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक संसाधन और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया।कार्यक्रम का समापन गौरवपूर्ण माहौल में हुआ, जहां जनरल ऑफिसर कमांडिंग एवं जिला मजिस्ट्रेट ने कैडेट रघुवेंद्र प्रताप सिंह को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA-II 2025) में चयनित होने पर सम्मानित किया। इस अवसर पर उनकी मेहनत, अनुशासन और उत्कृष्ट उपलब्धि की सराहना की गई।

पोक्सो मामले में बंदी साई भगीरथ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

संवाददाता

हैदराबाद। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) मामले में आरोपित बंदी साई भगीरथ को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के बाद उन्हें चेरलापल्ली सेंट्रल जेल स्थानांतरित कर दिया गया। इससे पहले आरोपी ने पेटबशीराबाद पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे अदालत में पेश किया। साइबराबाद पुलिस के अनुसार, बंदी साई भगीरथ को तेलंगाना राज्य पुलिस अकादमी (टीएसपीए) जंक्शन के पास से हिरासत में लिया गया और कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच वाहन काफिले के जरिए पेटबशीराबाद पुलिस स्टेशन लाया गया।

मामले की निगरानी कर रहीं कुकटपल्ली की पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) रीतिराज भी इस दौरान पुलिस स्टेशन पहुंचीं और जांच की प्रगति की समीक्षा की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपित को मेडिकल जांच के लिए मेडचल स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। मेडिकल परीक्षण के बाद उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया,

जहां अदालत ने आरोपी को 29 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। मामले में नया मोड़ तब आया जब आरोपित के कानूनी सलाहकार और अधिवक्ता करुणा सागर ने दावा किया कि केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के निर्देश पर वह साई भगीरथ के साथ अप्पा जंक्शन पहुंचे थे। वहां उन्होंने आरोपित को साइबराबाद पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस टीम (एसओटी) के हवाले किया। अधिवक्ता के अनुसार, इसके बाद पुलिस आरोपित को पेटबशीराबाद थाने ले गई। करुणा सागर ने कहा कि बचाव पक्ष अगले कार्य दिवस पर अदालत में जमानत याचिका दाखिल करेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और उनका मुवक्किल इस मामले में निर्दोष साबित होगा।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों के कसे पेंच, कार्ययोजना बनाकर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के दिए निर्देश

देवेश प्रताप सिंह राठौर

झांसी, उत्तर प्रदेश। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में कर-करेत्तर एवं प्रवर्तन कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी विभाग कार्ययोजना बनाकर वित्तीय वर्ष 2026-27 के निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि मासिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए वसूली में तेजी लाई जाए, ताकि जनपद को दिए गए वार्षिक लक्ष्य पूरे किए जा सकें।बैठक में वाणिज्य कर, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, मालकर/वाहनकर/यात्रीकर, राज्य उत्पाद शुल्क (आबकारी), अलौह खनन एवं धातुकर्म तथा वानिकी एवं वन्यजीव विभागों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

वाणिज्य कर विभाग की धीमी वसूली पर नाराजगी

जिलाधिकारी ने वाणिज्य कर विभाग द्वारा अप्रैल माह में निर्धारित 187.79 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 107.77 करोड़ की वसूली पर नाराजगी जताई। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जीएसटी चोरी के मामलों पर प्रभावी कार्रवाई करने और कर अपवंचन रोकने के प्रयासों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायतीराज विभाग और निकायों में टीडीएस एवं जीएसटी कटौती संबंधी कार्यशाला आयोजित करने की जिम्मेदारी भी वाणिज्य कर विभाग को सौंपी।

आबकारी विभाग को आरसी वसूली तेज करने के निर्देश

राज्य उत्पाद शुल्क (आबकारी) विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने शादी-विवाह एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए एक दिन का लाइसेंस जारी करने पर जोर देते हुए विभागीय अधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमण कर सर्वे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग की निर्गत आरसी की वसूली में तेजी लाई जाए। विभाग द्वारा 60.48 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 62.13 करोड़ की वसूली किए जाने पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन अधिकारियों को निरंतर सक्रिय रहने की नसीहत भी दी। जिलाधिकारी ने शराब की दुकानों का सत्यापन कर गंदगी पाए जाने पर जुर्माना लगाने तथा गांजा बिक्री की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षण संस्थानों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री रोकने पर भी विशेष जोर दिया।

ओवरलोडिंग और वाहन कर वसूली पर सख्ती

मालकर, वाहन कर एवं यात्री कर की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने डंपरों के चालानों की सूची तैयार कर वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। विभाग द्वारा 16.49 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 15.36 करोड़ की वसूली पर असंतोष जताते हुए प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर चालान एवं वसूली कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए।

पेयजल व्यवस्था बाधित न हो

बैठक में जिलाधिकारी ने निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए कि भीषण गर्मी को देखते हुए कहीं भी पेयजल आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या है, वहां तत्काल टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आयुष सैनी, एडीएम वित्त एवं राजस्व वरुण कुमार पाण्डेय, एडीएम प्रशासन शिव प्रताप शुक्ल, एडीएम न्याय अरुण कुमार गौड़, नगर मजिस्ट्रेट प्रमोद झा, जिला आबकारी अधिकारी मनीष गुप्ता, जिला खनिज अधिकारी शैलेंद्र सिंह, विद्युत विभाग के अधिकारी, समस्त एसडीएम तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मालिक, प्रकाशक व मुद्रक- सुनील कुमार तिवारी द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट नं. ०४, ग्राउंड फ्लोर, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, ऑफ आरे रोड, नियर प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गेट नं ०२, गोरेगांव (पूर्व) मुंबई-४०००६३ से मुद्रित व ६१७, बिल्डिंग नं. १४ नियर शिव शक्ति बिल्डिंग, गोलीबार रोड, सान्ताक्रूज (पूर्व), मुंबई-४०००५५ से प्रकाशित। **संपादक सुनील कुमार तिवारी,** RNI. NO. MAHMUL/2017/74054, **संपादकीय कार्यालय: कंटेश्वर सिंह चाल, अपोजीट एकताड़ मंडल, साईं बाबा रोड, खार (पूर्व), मुंबई- 400051, Mob. 8898271111**